04 - फ़िलेमॉन यैंग की भारत यात्रा और ....

05 -अध्यात्म और सनातन के चरमोत्कर्ष का दौर और दुर्घटना

A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025

06 - दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया त्यौहार

07 - गुना में श्रद्धालुओं की ट्रॉली पलटी

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-158 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

प्रसंगवश

आर्थिक नुकसान से बचने ऐसी हो राज्यों में आपदाओं की तैयारी

टीम डाउन टू अर्थ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने आपदाओं के कारण भारत के 25 राज्यों में होने वाले आर्थिक नुकसान का पता लगाया है। बदलती जलवायु की वजह से आपदाएं और चरम मौसम की घटनाएं, जैसे कि लू या हीटवेव, सूखा और जंगल की आग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, बुनियादी ढांचे और लोगों की बस्तियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने इन आपदाओं के कारण भारत के 25 राज्यों में होने वाले आर्थिक नुकसान का पता लगाया है।

पिछले 23 सालों की अवधि को शामिल करने वाले इस अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि किस तरह से राज्यों के बजट को सालाना गंभीर रूप से असर डालती है। यह शोध आपदा की बेहतर तैयारी और आर्थिक सुरक्षा के लिए समाधान भी देता है, साथ ही ऐसे संकटों से होने वाले आर्थिक नुकसान के नतीजों को कम करने में मदद करने के लिए एक रोडमैप भी प्रदान करता है।

शोध पत्र के हवाले से शोधकर्ता ने कहा कि आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान, मौतों की संख्या और प्रभावित लोगों की संख्या के मूल्यांकन के आधार पर नुकसान का अनुमान लगाया जाता है। ये मूल्यांकन अक्सर सही नहीं होते हैं। शोध में चक्रवात की ताकत और बाढ़ की गंभीरता को सटीकता से मापने के लिए मौसम और भौगोलिक स्रोतों के आंकड़ों का उपयोग किया गया।

'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन' में प्रकाशित शोध के मुताबिक, इस जानकारी के आधार पर शोधकर्ताओं ने एक आपदा तीव्रता सूचकांक (डीआईआई) बनाया, जिससे यह साफ हो गया कि सभी तरह की आपदाओं का निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाए।

यह विधि विसंगतियों और पूर्वाग्रहों से बचती है और आपदा प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर देती है, खासकर बाढ़ और चक्रवातों के लिए, जिनके कारण अध्ययन अवधि के दौरान भारत में आपदा से संबंधित 80 फीसदी तक नुकसान देखा गया। अध्ययन में बताया गया है कि इसमें पैनल वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) नामक सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक साल से लेकर अगले कुछ सालों तक राजस्व और व्यय एक दूसरे पर किस तरह असर डालते हैं।

यह मॉडल राज्यों के बीच अंतरों को ध्यान में रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि पिछली आर्थिक स्थितियां आपदा की गंभीरता के माप को गलत तरीके से प्रभावित न करें, जिससे आपदाओं के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने का एक विश्वसनीय तरीका हासिल होता है। अध्ययन से पता चलता है कि आपदाएं प्रभावित राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डालती हैं, क्योंकि इससे उनका खर्चा बढ़ जाता है और साथ ही उनका राजस्व भी कम हो जाता है। जिसके कारण राज्य तत्काल राहत प्रयासों जैसे कि निकासी, चिकित्सा सहायता, भोजन और आश्रय के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करते हैं।

सरकार सड़कों, पुलों और घरों जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में भी निवेश करती है। क्योंकि इन आपदाओं के कारण कृषि, व्यापार और व्यावसायिक को चलाने में अक्सर रुकावट आती है, इसलिए इन क्षेत्रों से कर संग्रह और आय में भी कमी आती है। अध्ययन एक ऐसे चक्र पर प्रकाश डालता है जिसमें व्यय में वृद्धि और राजस्व में गिरावट के कारण बजट में भारी घाटा होता है।

शोध में कहा गया कि आपदा तीव्रता सूचकांक (डीआईआई) से पता चलता है कि आपदाएं राज्यों पर अलग-अलग तरीके से असर डालती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कम आपदा-प्रवण राज्य, जो सूखे और कभी-कभी बाढ़ का सामना करते हैं, अपने स्वयं के संसाधनों से राहत का प्रबंधन कर सकते हैं और उनकों आर्थिक नुकसान कम होता हैं।

आपदा की तीव्रता लोगों की आय या उत्पादन को प्रभावित करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए कर या बिना-कर के राजस्व में कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे आपदा-प्रवण तटीय राज्य, जो अक्सर चक्रवात और बाढ़ का सामना करते हैं, में खर्च और राजस्व घाटा अधिक होता है। नतीजतन, उन्हें अक्सर ऋण जैसे बाहरी वित्तपोषण पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे राज्य का कर्ज बढ़ता है और अन्य विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना मुश्किल हो जाता है।

शोध में सुझाव देते हुए कहा गया है कि राज्यों को पूर्व चेतावनी प्रणाली, चक्रवात आश्रयों और बुनियादी ढांचे में निवेश करने और टिकाऊ भूमि उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव को कम कर सकता है। साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए लंबे समय तक होने वाले खर्चों को कम कर सकता है। शोध के मुताबिक, कई राज्यों ने पहले ही इसे लागू कर लिया है, तमिलनाडु ने उन्नत चक्रवात निगरानी प्रणाली स्थापित की है, केरल ने जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन को अपनाया है और ओडिशा और कई अन्य ने जलवायु-संबंधी खर्च के लिए बजट ट्रैकिंग शुरू की है।

जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी जारी है, इसलिए शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भारतीय राज्यों को और भी बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सुझाए गए उपायों को अपनाकर भारत लंबे समय तक आर्थिक खतरों को कम किया जा सकता है।

सतत विकास, आपदा के खतरों को कम करने के लिए दुनिया भर में आम सहमति बनाने, अध्ययन में आपदा जोखिम वित्तपोषण (डीआरएफ) के अनुरूप राष्ट्रीय नीतियों को बनाने और चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है।

यह सरकारों के लिए तत्काल आपदा प्रतिक्रिया को राजकोषीय नीतियों के प्रबंधन के साथ-साथ प्रभावित आबादी की तत्काल जरूरतों का प्रबंधन करने पर जोर देता है। यह जीवन और बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सकता है और एक मजबूत, अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

(डाउन टू अर्थ हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

आचार्य विद्यासागर जी अपने जीवन काल में ही देवता के रूप में स्वीकारे जाने लगे थे

भोपाल में बनेगा संत शिरोमणी का स्मृति स्थल : मुख्यमंत्री

● मुख्यमंत्री ने विद्यासागर जी महाराज के जीवन और कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया ● मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर किया संबोधित ● मुख्यमंत्री*ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के प्रथम स्मृति दिवस पर विधानसभा परिसर के कार्यक्रम में संतों से आशीर्वाद लिया।

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की स्मृति में भोपाल में स्मृति स्थल विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर विधानसभा परिसर में आयोजित गुरु गुणानुवाद सभा में गुरु वंदना कर अतिशय पुण्य अर्जित करने पधारे समर्पित भक्तों का राज्य शासन की ओर से अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सभी आवश्यक नियमों का पालन किया। संत परंपरा का अनुसरण करते हुए उनके प्रकृति के साथ संबंध, जीवन शैली, मानव सेवा और समाज को मार्गदर्शन के माध्यम से वे अपने जीवन काल में ही देवता के रूप में स्वीकारे जाने लगे।

व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, सेवा, समर्पण जैसे शब्द उनके व्यक्तित्व के सम्मुख छोटे पड़ जाते हैं।

कार्यक्रम में सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह, जनप्रतिनिधि श्री राहुल कोठारी तथा जैन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित थे।

संत-श्री ने जीवन के कई क्षेत्रों में समाज को दिशा दी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपनी इच्छा शक्ति से जीवन के कई क्षेत्रों में समाज को दिशा दी। स्वरोजगार के क्षेत्र में जेल से लेकर समाज में महिलाओं को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त किया। गौ-माता की भी उन्होंने चिंता की तथा गौ-माता के माध्यम से लोगों के जीवन और प्रकृति में बदलाव के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में की गई उनकी पहल अनुकरणीय है। आचार्यश्री ने अपने विचार, भाव और कर्म से समाज को प्रकृति व परमात्मा के समान पुष्पित-पल्लवित, प्रेरित करने का कार्य किया।

भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें, नई शिक्षा नीति का आधार है- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत-श्री का विचार था कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। वे भाषाओं की समृद्धि पर विशेष ध्यान देते थे, उनका विचार था कि भाषाओं की विविधता की जानकारी से भारत की आंतरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है और ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि आवश्यक है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रदेश में निरंतर प्रयास जारी हैं, इस क्रम में 55 एक्सीलेंस कॉलेज आरंभ किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें, नई शिक्षा नीति का आधार है। इसी का परिणाम है की नई शिक्षा नीति में जैन दर्शन सहित भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी विचारों को शामिल किया गया है। प्रदेश में खुले में मांस की दुकानों को भी बंद किया गया। तेज ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री का मुकुट और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिगम्बर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं ने मुकुट तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया। उनको शॉल भी सम्मानपूर्वक भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्जवलित किया तथा मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन और कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्हें नेमावर में संत-श्री के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साक्षात देवता के दर्शन के समान प्रतीत होता संत-श्री का अलौकिक व्यक्तित्व जीवन को धन्य करने वाला था। जैन और सनातन दर्शन में आत्मा की भूमिका आवागमन की बताई गई है। यह माना जाता है कि वस्त्र बदलने के समान ही पवित्र आत्मा शरीर बदलती है। इस दृष्टि से यह मानना कि महाराज जी हमारे बीच नहीं है, व्यर्थ है।

शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश

खेत में गिरते ही मिराज-2000 में आग लगी, दोनों पायलट हादसे से पहले कूदे

शिवपुरी/ग्वालियर (नप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बहरेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का टू सीटर फाइटर प्लेन मिराज-2000 क्रैश हो गया। हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2.40 बजे हुआ। प्लेन में दो पायलट थे। हादसे से पहले दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट (बचकर निकले) कर लिया था। दोनों ही सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एयरफोर्स की टीम हेलिकॉप्टर से मौके पर पहुंची। विमान में पायलट विक्रांत जाधव और विंग कमांडर विराज भोला सवार थे। एयरफोर्स की टीम दोनों को लेकर ग्वालियर रवाना हो गई।

बताया जा रहा है कि तीन विमानों ने ग्वालियर से नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी। इनमें से दो प्लेन सुरक्षित लौट गए। एयरफोर्स ने हादसे की शुरुआती वजह सिस्टम में खराबी बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

शिवपुरी एएसपी संजीव मुले ने बताया किदोपहर में ग्रामीणों ने घटना की सूचना दी थी। जानकारी निकाली तो पता चला कि यह ग्वालियर एयरबेस का प्लेन था। इसमें दो पायलट थे, दोनों सुरक्षित हैं। कोई ग्रामीण इसमें घायल नहीं हुआ है। रेस्क्यू के लिए हेलिकॉप्टर आ गया, जो पायलट को ले गया है। घटना का कारण एयरफोर्स बेस से ही पता चल सकेगा।

सुप्रभात

सुबह की मीठी धूप और

फागुन की मादक हवाओं के बीच
मुरम की लाल कच्ची सड़क से पैदल
मैं अपने गाँव जाऊँगा
पेसेंजर से उतर कर।
रास्ते के उजड़े वन में
पलाश के फूलों की सिंदूरी
दमक में खो जाऊँगा
पीले खेतों को आँखों में भर लूँगा
नदी के बहते जल में अपना
अक्स निहारूँगा
अमराई में रूकूँगा कुछ देर
आम के बौर की सुगंध
नाक में भर लूँगा।
खेत में काम पर जा रही
एक ग्रामीण बाला से आँखें
चार करूँगा
वह मुस्कुराएगी तो खुशी से
झूम जाऊँगा।
छोटी-सी बैलगाड़ी में विदा हो
ससुराल जा रही दुल्हन का
घूँघट में छिपा चेहरा देखने
की कोशिश करूँगा।
घर पहुँचूँगा तो बिल्कुल थका
नहीं होऊँगा
फिर भी माँ से माँगूँगा
गिलास भर गुड़ की चाय।

चंद्रशेखर साकल्ले

दो ट्रक भिड़े, मां-बेटी और दंपती की मौत

● **आमने-सामने टक्कर में बुरी तरह पिचक गए वाहन, काफी देर तक फंसे रहे शव**

उमरिया (नप्र)। उमरिया में दो ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में मेटाडोर ट्रक में सवार दंपती और मां-बेटी की मौत हो गई। एक घायल है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह से पिचक गए। शव ट्रक में फंस गए, जिन्हें निकालने में पुलिस को काफी परेशानी आई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। हादसा पाली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ।

ट्रक में चावल और मेटाडोर में बिसलेरी थी

थाना प्रभारी मदनलाल मरावी ने बताया कि ट्रक शहडोल से आ रहा था, इसमें चावल लदा था। वहीं, मेटाडोर ट्रक में बिसलेरी भरी थी। मेटाडोर उमरिया की तरफ से आ रही थी। तभी आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में मेटाडोर चालक नरेंद्र चौधरी (21) गंभीर रूप से घायल है। पार्वती सिंह (47), उनकी बेटी चम्पा सिंह (20), सुदर्शन सिंह (52) और उनकी पत्नी शशिकला (48) की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी पाली से मुदरिया जा रहे थे।एएसपी प्रतिपाल सिंह ने बताया कि दो घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था।

मप्र को जल्द मिलेगा 9वां टाइगर रिजर्व

सीएम यादव बोले- माधव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने जारी होगी अधिसूचना

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि एमपी को जल्द ही 9वां टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद नए टाइगर रिजर्व की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

उन्होंने कहा कि नए टाइगर रिजर्व के बाद चंबल अंचल में भी वन्यजीवों की समृद्धि बढ़ेगी। इसके बाद देश भर में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की कैटेगरी में शामिल एमपी में एक और टाइगर रिजर्व बढ़ जाएगा। बुधवार को श्योपुर जिले के कूनो अभयारण्य से चीतों को खुले जंगल में छोड़ने के बाद सीएम यादव ने आज कहा कि वन्यजीव संरक्षण में मध्यप्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माधव टाइगर अभयारण्य जल्द ही राज्य

का 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा। इससे चंबल अंचल में वन्यजीवों की समृद्धि बढ़ेगी। कूनो नेशनल पार्क से अभी तक 7 चीतों को जंगल में स्वछंद विचरण के लिये छोड़ा गया है। कूनो में वीरा के 2 नए शावकों को मिलाकर कुल 26 चीते हो गये हैं। इन चीतों की मॉनिटरिंग के लिये 2 दल गठित किए गए हैं।

बुधवार को कूनो में 5 और चीते छोड़े गए हैं। यह गर्व की बात है कि पहले छोड़े गए चीते न केवल शिकार कर रहे हैं, बल्कि कुशलता से जंगल में विचरण कर रहे हैं। प्रकृति और संतुलन की यह अनमोल झलक हमारे प्रदेश में दिख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को नया टाइगर अभयारण्य मिलने वाला है। माधव टाइगर रिजर्व की काफी हद तक औपचारिकता पूरी कर ली गई हैं। कल पालपुर कूनो में चीते छोड़े गए हैं। अब तक पांच चीते छोड़े जा चुके हैं। चीतों में परिवार परम्परा है। नर चीते साथ रहे थे। दो मादा और तीन नर चीते एमपी की आबोहवा में खुद को ढाल रहे हैं।सीएम यादव ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि पालपुर-कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता 'आशा' और हाल ही में शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता 'वीरा' के 3 शावकों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चीतों की पुनर्स्थापना से कूनो की पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले 2 चीते खुले जंगल में छोड़े थे जिससे वन्य जीवन में चीतों की पुन-बसाहट हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज 5 चीतों को जंगल में छोड़ने का अवसर मिला है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c | न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार,07 फरवरी 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए 10 हजार करोड़ का एमओयू तैयार

● रक्षा समिति ने दी मंजूरी,तोपखानों को और मजबूत करने का है प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को आधुनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए हरी झंडी मिलती दिख रही है। भारतीय सेना के तोपखानों को और आधुनिक बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के गोला बारूद खरीदने के लिए मंजूरी मिलने वाली है। सुरक्षा को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय समिति ने रक्षा सौदे के इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी पिछले सप्ताह ही दे दी थी। इस फैसले के तहत दो भिन्न प्रकार के गोला-बारूद खरीदें जाएंगे। दुश्मन देशों को युद्ध क्षेत्र में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अपनी तैयारी में लगी रहती है। इसी कड़ी में भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 10,200 करोड़ रुपये से अधिक के पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणालियों के गोला बारूद खरीदने को लेकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की

तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के अंत में इस एमओयू पर मुहर लग सकती है। 31 मार्च से पहले इन दो बड़े अनुबंधों के तहत 5700 करोड़ का हाई-विस्फोटक प्री-फ्रैगमेंटेड गोला-बारूद और 4500 करोड़ रुपये का एरिया डिनायल म्यूनिशन का सौदा किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट के निर्यात के लिए कई देशों ने रुचि दिखाई है। इसे आर्मेनिया खरीद चुका है जबकि फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। इसकी सफलता एक बड़ी कहानी बनती जा रही है। इस रॉकेट सिस्टम के कई वैरिएंट उपलब्ध हैं। ये रॉकेट 75 किलोमीटर और उससे भी अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसकी सटीक मारक क्षमता दुनिया के सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में से एक है।

यूपी के गांव में मिला कच्चे तेल का भंडार!

कंपनी के अफसरों ने शुरू कराई बोरिंग, शुरू हुई तलाश

बदायूं (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से भारत देश के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आ सकती है। यहां कच्चे तेल की संभालना के मद्देनजर अल्फाजियों, इंडिया कंपनी ने सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उक्त कंपनी अफसरों ने जिले के उघैती इलाके के गांव टिटौली में पिछले कई दिनों डेरा डाल

रखा है और यहां कच्चे तेल की खोज करना शुरू कर दिया है। अफसर यहां बोरिंग की गहराई मापने के जरिए पानी निकालकर कच्चे तेल की खोजबीन के रहस्य का पता लगाने की खोज कर रहे हैं। इससे जनपद में कच्चे तेल की संभावनाओं की अटकलें शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अल्फा जियो यानि की इंडिया कंपनी के अफसर यहां पिछले कई दिनों से जनपद के अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर सर्वे के लिए डेरा डालकर डटे हुए हैं। इंडिया कंपनी के अफसर विभिन्न क्षेत्रों पर वैज्ञानिक तरीकों से बोरिंग कर कच्चे तेल की खोज के लिए यहां प्रयासरत हैं। इसके लिए वो गहराई से पानी निकालकर नमूना ले रहे।

हमारा एजेंडा सबका साथ-सबका विकास: पीएम मोदी

राज्यसभा में पीएम ने कहा-कांग्रेस रंग बदलने में है माहिर

कहा-कांग्रेस मॉडल में फैमिली फर्स्ट,हमारे लिए नेशन फर्स्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की है, देश को आगे की दिशा भी दिखाई है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सबके लिए भविष्य के काम पर मार्गदर्शक भी था। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे इसके लिए कोई अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच, समझ के बाहर है और रोडमैप में भी सूट नहीं करता।

मातृभाषा में परीक्षा करवाई, बेटियों के लिए खुले सैनिक स्कूल

मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा कराई। गुलामी की मानसिकता के कारण गरीब बच्चों के साथ अन्याय था। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र से हमने यह बदलाव लाया। आदिवासी युवाओं के लिए मॉडल स्कूलों का विस्तार किया है। आज 470 एकलव्य स्कूल हैं। 200 और बन रहे हैं। सैनिक स्कूलों में हमने बेटियों के लिए भी प्रवेश की व्यवस्था की है। पहले बेटियों के लिए इनके दरवाजे बंद थे।

● मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है

स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान मिडिल क्लास के हैं। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित हैं। खासतौर पर जी 20 के सदस्य देश आकर्षित हैं। विश्व का टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इसका लाभ मिडिल क्लास को मिलेगा। हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मुझे विश्वास है। भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के लिए हमारे साथ चल पड़ा है। विकसित भारत में सबसे बड़ा रोल युवाओं का है। जो स्कूल कॉलेज में है, वही विकसित भारत के लाभार्थी बनने वाले हैं। पिछले 10 साल में इस तबके को मजबूत करने के लिए बहुत सोची समझी रणनीति से काम किया है। शिक्षा नीति के लिए कभी सोचा नहीं गया। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। हम 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं। इसका लाभ मिडिल क्लास को मिल रहा है। हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर देशवासियों को दिए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर बनाने वालों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया है। वहां मिडिल क्साल के पैसे फंसे हैं।

म्यांमार सीमा पर कंटीले तार लगाने का हो रहा है विरोध

● पूर्वोत्तर के तीन राज्यों ने अभी शुरू नही किया काम, जता रहे नाराजगी ● नगा संगठन की चेतावनी- प्रोजेक्ट में काम किया तो गंभीर नतीजे होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। म्यांमार से लगी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की 1,643 किमी लंबी सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो गया है। इसी कारण 4 में से 3 राज्यों में अभी काम भी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं, चौथे राज्य मणिपुर में अब तक 37 किमी ही बाड़ लग पाई है। नगालैंड, मिजोरम में तो स्थानीय संगठन खुलकर विरोध में उतर आए हैं।

नगाओं के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड नगा काउंसिल ने स्थानीय लोगों को कह दिया है कि यदि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया, तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पिछले साल भी संगठनों ने लोगों को प्रोजेक्ट का विरोध करने को कहा था, लेकिन तब काम करने पर पाबंदी नहीं लगाई थी। यही हाल मिजोरम में है। दोनों राज्यों में बाड़ का सर्वे भी शुरू नहीं हो पाया है। अरुणाचल में सर्वे हो रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के एक अधिकारी ने बताया कि मणिपुर के टेंगनाउपोल में म्यांमार से सटे फाइको और थाना गांव में लोग बाड़ के खिलाफ थे, लेकिन टीम ने सर्वे नहीं रोका।

मालदीव में भारत की नई चाल से चीन खा जाएगा मात

हिंद महासागर में ड्रैगन की बढ़ेगी मुश्किल, जबर्दस्त है प्लान

माले (एजेंसी)। हिंद महासागर में स्थित अपने पड़ोसी मालदीव में चीन की चालबाजी को मात देने के लिए भारत बेहद ही सधी हुई चाल चल रहा है। फरवरी की शुरुआत में जारी अपने नए बजट में मालदीव के लिए अपनी वित्तीय मदद में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। विशेषज्ञों ने इसे क्षेत्र में चीन के प्रभाव को पीछे छोड़ने की दिशा में अहम प्रयास बताया है। 1 फरवरी को जारी

भारत के 2025 के राष्ट्रीय बजट में मालदीव को 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 470 करोड़ से काफी ज्यादा है। यह अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में सबसे बड़ी वृद्धि है। हालांकि, भारत ने पिछले साल के अपने बजट में शुरुआत में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, लेकिन मालदीव के मंत्रियों की पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों ने कूटनीतिक विवाद को जन्म दिया। इसके बाद भारत ने वित्तीय सहायता राशि को घटाकर 470 करोड़ रुपये कर दिया था। नवम्बर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के साथ ही मालदीव के संबंध भारत से खराब होने शुरू हो गए थे। चीन परस्त मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव के पहले इंडिया आउट अभियान चलाया था। मुइज्जू ने भारतीय सैन्य अधिकारियों का विरोध किया।

अमरीका ने 16 सालों में 15,652 भारतीयों को वापस भेजा

जयशंकर बोले-यूएस से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं

कांग्रेस का आरोप-नागरिकों से आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संसद में जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस (स्वदेश) बुलाना सभी देशों का दायित्व है। विदेश मंत्री ने बताया, अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। यह 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका ने 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को एक दिन पहले 5 जनवरी को भारत भेज दिया। इन्हें स्र मिलिट्री का सी-17 प्लेन से पंजाब के अमृतसर

भेजा गया। इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी, जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। इसके बाद विपक्ष ने संसद के दोनों में हंगामा और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों के कई सारे सांसदों ने अमेरिका में अवैध तरीके से भारतीयों को वापस भेजने के तरीके पर सवाल खड़े किए। बुधवार को एक अमेरिका का सैन्य विमान 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा। निर्वासित लोगों ने दावा किया कि उनके हाथ और पैरों में हथकड़ी लगी थी।

भारत के सपने को ट्रंप ने दिया एक और बड़ा झटका

ईरान के चाबहार पोर्ट पर चलाया हथौड़ा, पाकिस्तान होगा खुश

तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म कर दे। इससे पहले अमेरिका ने अशरफ गनी सरकार के रहने के दौरान भारत को अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रतिबंधों में छूट दी थी। इसके बाद भारत ने इस ईरानी बंदरगाह को बनाने में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। भारत इसी बंदरगाह के रास्ते रूस से सीधे इंटरनेशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते जुड़ रहा है। यही नहीं भारत का अफगानिस्तान तक माल भेजने का सबसे बड़ा रास्ता है। भारत इसे मध्य एशिया तक जाने के लिए एक रास्ते के रूप में विकसित कर रहा है।

बिना डरे आतंकियों का करो खात्मा अमित शाह का सुरक्षाबलों को निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। बुधवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने आतंकवाद की फंडिंग में नशीले पदार्थों की भूमिका पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को नशीले पदार्थों के व्यापार से पैसा मिलता है। इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मौजूद थे। गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, और इंटेलीजेंस ब्यूरो के निदेशक भी शामिल हुए। यह बैठक मंगलवार को शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक का ही अगला भाग थी, जिसमें थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उपस्थित थे। यह लगातार दो बैठकें दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद हुईं। इस हमले में पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे शहीद हो गए थे जबकि उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार घायल हो गए थे। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में निरंतर और समन्वित प्रयासों से आतंकवाद का ढांचा काफी कमजोर हुआ है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से टेररिस्ट फंडिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

● जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने का शाह का निर्देश

● शाह बोले-युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

महाकुंभ भगदड़

हादसा नहीं, साजिश मानकर जांच कर रहीं एजेंसियां

एटीएस के रडार पर 10 हजार संदिग्ध,सीएए-एनआरसी के प्रदर्शनकारियों पर पैनी नजर

वाराणसी (एजेंसी)। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ रही है। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं, साजिश मानकर जांच कर रही हैं। यूपी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस), स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और लोकल इंटेलीजेंस यूनिट के रडार पर 10 हजार से ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनमें से कई का मूवमेंट मिला है। जांच में ऐसे गैर हिंदू हैं, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पर महाकुंभ को लेकर निगेटिव कमेंट किए गए, या फिर उन्होंने गूगल और यूट्यूब पर महाकुंभ को बहुत ज्यादा सर्च किया।

इनकी भूमिका की भी जांच एटीएस और एसटीएफ कर रही हैं। 18 जेलों में कैद सिमी सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों को आना था। बड़ा आयोजन था, इसलिए महीनों पहले से खुफिया एजेंसियां ऐक्टिव थीं। इंटेलीजेंस ने सीएए, एनआरसी के प्रदर्शनकारी, क्रिमिनल हिस्ट्री, प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इनपुट दिए थे। इसके आधार पर यूपी के 1 लाख से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया। उन्हें समझाया गया और मैसेज दिया गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की तरफ मूवमेंट नहीं करें। इसके बावजूद भगदड़ होने के बाद जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ का मूवमेंट महाकुंभ में हुआ। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ वाराणसी और आसपास के 10 जिलों के 16 हजार लोगों को महाकुंभ से पहले ही काशी के बाहर मूवमेंट करने से मना किया गया, लेकिन, 117 लोगों का मूवमेंट काशी के बाहर मिला। इनमें 50 से ज्यादा लोग प्रयागराज भी पहुंचे थे। ये सभी हिंदू धर्म से नहीं हैं। जब लोगों से पूछताछ हुई, तब उन्होंने अपने मूवमेंट के पीछे अलग-अलग कारण बताए।

● **जेल से डेटा मांगा, एजेंटों से हो रही पूछताछ-** महाकुंभ को लेकर एटीएस, एसटीएफ और एनआईए ने जांच के लिए बड़ा डोजियर तैयार किया है। इसमें सीएए-एनआरसी, सिमी के अलावा पुलिस और आर्मी इंटेलीजेंस द्वारा पकड़े गए संदिग्ध एजेंट भी शामिल हैं। देश के विभिन्न जगहों से पिछले 6 महीने में पकड़े गए एजेंटों की जेलों में पूछताछ की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले कुछ लोग जेल गए थे। जेलों से उनका डेटा निकलवाया जा रहा है। उनसे वन-टु-वन पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में ही ऐसे 70 लोगों को डेटा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, सेंट्रल यूपी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जेलों से भी ये डेटा मांगा गया है। जिसमें विरोध करने वाले जेल गए थे। वाराणसी डीएम ने पिछले दिनों जैतपुरा के अमानतुल्लाह निवासी नेता शाहिद जमाल के बेटे सिराजुद्दीन को नोटिस जारी किया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया से राजगढ़ जिले की सोलो साइक्लिस्ट एवं एथलीट आशा मालवीय ने सौजन्य भेंट की।

आनंद शिविर में भाग लेने देश की चार संस्थाओं में जा सकते हैं शासकीय सेवक

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आनंद विभाग लोगों के जीवन को टेन्शन फ्री कर उनके जीवन में आनंद के लिए कार्य कर रहा है। शासकीय सेवकों में आनंद शिविर से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राज्य आनंद संस्थान द्वारा वर्तमान में देश की 4 संस्थाओं से एमओयू किया गया है। इन संस्थाओं में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउण्डेशन बैंगलूरू, इनिशिएटिव ऑफ चेंज पुणे, दशा (फाउंडेशन) गोगा सेन्टर कोयम्बटूर, हार्टफुलनेस इंस्टिट्यूट (कान्हा शान्तिवनम) हैदराबाद शामिल हैं। आनंद शिविर में भाग लेने के लिए आनंद विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। आनंद शिविर में पंजीयन करवाते समय शासकीय सेवकों को नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। आनंद शिविरों के माध्यम से व्यक्तियों को आनंद के साथ परिपूर्ण जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। चारों संस्थानों के साथ 5 आनंद शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 184 प्रतिभागियों की सहभागिता रही।

राज्य सरकार शिल्पियों को कर रही है प्रोत्साहित

- **मध्यप्रदेश के बाग प्रिंट शिल्पियों ने पुणे में विरासत हाट मेले में की भागीदारी**

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के शिल्पियों को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग शिल्पियों एवं हाथकरघा बुनकरों को देश के विभिन्न मेलों और उत्सवों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इससे प्रदेश की कला की देश में सराहना हो रही है। प्रदेश के बाग प्रिंट शिल्पियों ने पुणे में आयोजित विरासत हाट मेले में सहभागिता की। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पगुरू श्री मोहम्मद युसुफ खत्री और श्री अब्दुल करीम खत्री ने भी भागीदारी की। प्रमुख हस्तियों ने शिल्पियों का मनोबल बढ़ाकर सराहना की। शिल्पियों का प्रदेश की बाग प्रिंट की लोकप्रियता महाराष्ट्र में फैलाने में अहम योगदान रहा।

गेहूँ उपार्जन: 62 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

- **गेहूँ उपार्जन के लिये 31 मार्च तक होगा पंजीयन-खाद्य मंत्री राजपूत**

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 62 हजार 77 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2025-26 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रूपये अधिक है। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूँ की विक्री के लिए समय-सीमा में पंजीयन जरूर करायें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिए जिला बुरहानपुर में 2, बड़वानी में 17, खरगोन में 189, खंडवा में 339, अलीराजपुर में 13, झाबुआ में 776, धार में 4202, इंदौर में 9381, नीमच 134, मंदसौर 362, आगर-मालवा में 823, शाजापुर में 3710, देवास में 4035, रतलाम में 2211, उज्जैन में 11344, ग्वालियर में 55, शिवपुरी में 23, गुना में 23, दतिया में 142, अशोकनगर में 6, भिंड में 4, मुरैना में 96, श्योपुर में 43, छिंदवाड़ा में 157, सिवनी में 61, डिंडौरी में 21, कटनी में 14, नरसिंहपुर में 215, मंडला में 353, हरदा में 173, बैतूल में 362, नर्मदापुरम में 1793, विदिशा में 1563, राजगढ़ में 1096, रायसेन में 1969, भोपाल में 1975, सीहोर में 12596, सतना में 48, सीधी में 75, रीवा में 44, सिंगरौली में 19, मैहर में 3, उमरिया में 64, अनूपपुर में 9, शहडोल में 239, पन्ना में 37, सागर में 419, दमोह में 124, छतरपुर में 289, निवाड़ी में 88 और टीकमगढ़ में 341 किसानों ने पंजीयन कराया है।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने किया माली समाज के केलेण्डर का विमोचन

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गुरुवार को निवास कार्यालय पर संयुक्त माली-सैनी-मरार समाज के केलेण्डर का विमोचन किया। संयुक्त माली-सैनी-मरार समाज के अध्यक्ष श्री जी.पी. माली, उपाध्यक्ष श्री राम नाराण चौहान, महासचिव श्री राजेन्द्र कुमार अंबाडकर और श्री प्रकाश मालवीय सहित समाजजन मैजूद थे।

आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंत्रालय में 'पुरस्कार चयन समिति'की बैठक हुई।

औद्योगिक विकास के नये युग की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री

- **ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहली बार होंगी सेक्टर वाइस समिट**
- **विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक होंगे एक मंच पर**

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश अपने रणनीतिक प्रयासों से औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर है। निवेशकों को अधिक प्रभावी अवसर देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के प्रमुख 6 सेक्टर्स पर केंद्रित समिट के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। यह पहली बार होगा जब हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और निवेशक एक मंच पर आकर विशेषज्ञ चर्चाओं, अवसरों और नीतिगत सुधारों पर संवाद करेंगे। इससे निवेश प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाया जा सकेगा।

देश का आकर्षक डेस्टिनेशन बनता मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, विकसित बुनियादी ढांचा और उद्योग-अनुकूल नीतियां इसे निवेश के लिए देश का सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बनाती हैं। शहरी विकास, पर्यटन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और एमएसएमई, ये सभी क्षेत्र अपनी असीमित संभावनाओं और अनुकूल वातावरण से निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश न केवल देश का पहला डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बल्कि ग्रीन एनर्जी हब, विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र और उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। इन विभागीय समिट से सरकार निवेशकों को नीतिगत प्रोत्साहन, संसाधनों की उपलब्धता और औद्योगिक ईको सिस्टम की मजबूती से अवगत कराएगी। इससे जीआईएस में होने वाली चर्चाएं वास्तविक निवेश प्रस्तावों में तब्दील हो सकेंगी।

शहरी विकास समिट

मध्यप्रदेश का शहरी बुनियादी ढांचा तेजी से सुदृढ़ हो रहा है। राज्य की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक्स हब इसे एक आदर्श रियल

एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश डेस्टिनेशन बना रहे हैं। जीआईएस में शहरी विकास समिट के माध्यम से स्मार्ट और सतत् शहरों के निर्माण पर केंद्रित चर्चा होगी, जिससे नवाचार और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन समिट

मध्यप्रदेश को 'भारत का दिल' कहा जाता है और इसके धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण पर्यटन क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खजुराहो, उज्जैन, साँची, पचमढ़ी, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध कराने के लिये तैयार हैं। पर्यटन समिट में हॉस्पिटैलिटी, थीम-बेस्ड डेस्टिनेशन और एडवेंचर टूरिज्म में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गहन चर्चा होगी।

माइनिंग समिट

मध्यप्रदेश खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यह देश में डायमंड, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज और तांबे का प्रमुख उत्पादक है। पन्ना स्थित एशिया की एकमात्र डायमंड माइंस और विशाल कोयला भंडार राज्य को माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन बनाते हैं। जीआईएस में माइनिंग समिट से खनन आधारित उद्योगों, मूल्यवर्धित प्र-संस्करण और नीतिगत प्रोत्साहनों पर चर्चा होगी।

रिन्यूएबल एनर्जी समिट

मध्यप्रदेश ग्रीन एनर्जी हब बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। रीवा सोलर प्लांट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और ग्रीन हाइड्रोजन में हो रहे विकास इसे नवकरणीय ऊर्जा निवेशकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। जीआईएस में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी समिट में सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए ठोस रणनीतियां प्रस्तुत की जाएंगी।

आईटी एंड टेक्नोलॉजी समिट

मध्यप्रदेश अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन का केंद्र बन रहा है। इंदौर आईटी हब, डेटा सेंटर पॉलिसी, स्टार्ट-अप ईको सिस्टम और उभरते एआई और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्रों में तेजी से निवेश आ रहा है। जीआईएस में आईटी समिट के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी पार्क और नई टेक्नोलॉजीज पर निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया जाएगा।

एमएसएमई समिट

मध्यप्रदेश का एमएसएमई सेक्टर राज्य की आर्थिक रीढ़ है, जहां लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्यरत हैं। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना, नए क्लस्टर और निर्यात प्रोत्साहन नीतियां इसे निवेश के लिए एक डेस्टिनेशन बना रही हैं। एमएसएमई समिट में उद्योगों को वित्तीय सहयोग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और नए बाजारों तक पहुंच को लेकर चर्चा होगी।

प्रवासी समिट

मध्यप्रदेश प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के उद्योग, स्टार्ट-अप, पर्यटन, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया है। यह समिट न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रभारी मुख्य अभियंता की प्रॉपर्टी कुर्क

ने दीपक असाई और पत्नी की एफडी, बीमा पॉलिसी भी कुर्क, इंदौर में भी कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने लोक निर्माण विभाग के पूर्व अधीक्षण यंत्री दीपक असाई के खिलाफ पीएमएलए में कार्रवाई की है। असाई की एक करोड़ पांच लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की गई है। जिसका बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपए है। इंदौर ईडी टीम ने अवैध सट्टेबाजी मामले में मनोज मालवीय की एक करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी कुर्क की है।

लोक निर्माण विभाग भोपाल में प्रभारी मुख्य अभियंता रहे अधीक्षण यंत्री दीपक असाई की यह संपत्ति महाराष्ट्र के भंडारा जिले में है। यह आवासीय और कॉमर्शियल यूज वाली दुकानों के रूप में है। साथ ही डाकघर में रखी गई इनकी और पत्नी के स्वामित्व वाली एफडी और एसएससी के रूप में चल संपत्ति और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की बीमा पालिसी भी कुर्क की गई हैं। लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा इनके विरुद्ध दर्ज अपराध के मामले में जांच के बाद यह कुर्की की कार्रवाई की गई है।

पति के अवैध काम में सहयोग करने पर पत्नी की भी प्रॉपर्टी कुर्क-ईडी की जांच में पता चला है कि दीपक असाई ने लोक निर्माण विभाग में लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहने के दौरान पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार से अवैध रूप से कमाई की। कमाई की इस रकम को बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्ति अर्जित करने में निवेश किया गया। ईडी के प्रेस नोट में कहा गया है कि असाई की पत्नी ज्योति असाई ने कथित तौर पर अपने पति की अवैध आय को वैध रूप में परिवर्तित करने में सहायता की है।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस सिवनी में 1 से 4 मार्च तक

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया हैकि विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस पेंच जिला सिवनी में एक से 4 मार्च तक आयोजित की जायेगी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 25 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने बताया है कि कॉन्फ्रेंस में विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त स्थनीय निकायों के निर्वाचन के दौरान आयीं चुनौतियों तथा उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नवाचारों और सुधारों से भी अवगत करायेंगे। इस दौरान स्थानीय निकायों के निर्वाचन में नई तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा होगी।

कर्मचारियों के वित्तीय अधिकार, पेंशन और सेवा नियमों में होगा बदलाव,प्रारुप तैयार

भोपाल, नप्र। राज्य सरकार सरकारी विभागों में पदस्थ कर्मचारियों की पेंशन, अवकाश नियमों और वित्तीय अधिकारों में परिवर्तन करने जा रही है। इसके लिए प्रारंभिक प्रारुप तैयार हो गया है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के सचिव, संचालक पेंशन और रेरा के वित्तीय सलाहकार के साथ चर्चा कर इन्हें अंतिम रुप देंगे। पेंशन,अवकाश और वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग एक के नियमों का पुर्नलेखन और इन्हें अद्यतन किया जा रहा है। इसके लिए एक समिति का गठन वित्त विभाग ने किया है। जो बदलाव और परिवर्तन किया जाना है उसका प्रारंभिक प्रारुप तैयार होकर वित्त विभाग के पास आ गया है। अब वित्त विभाग के प्रमुख सचिव समिति द्वारा प्रारुपित नियमों पर प्रारंभिक विचार विमर्श सात फ रवरी को करने वाले है। दोपहर तीन बजे उन्होंने वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा तथा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाईकर को इस प्रारुप पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। बैठक में वित्त विभाग के उपसचिव पीके श्रीवास्तव, परामर्शी वित्त अजय चौबे, आरके जैन और एमके बातव परामर्शी सेवा एवं वित्तीय नियमों के पुर्नलेखन दल के सदस्य भी शामिल होंगे।

नीमच में तहसीलदार ने किया जनपद पंचायत सीईओ का अपहरण

नागदा में दो जिलों की पुलिस ने घेरकर छुड़ाया, तहसीलदार, 5 पटवारी समेत 13 पर केस

उज्जैन (नप्र)। नीमच में कुछ लोगों ने जावद जनपद पंचायत के सीईओ आकाश धारवे (32) का अपहरण कर लिया। वे उन्हें काली स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर इंदौर की तरफ भागे। नागदा में उज्जैन और नीमच पुलिस ने घेराबंदी कर सीईओ को छुड़ाया। इस मामले में बेटमा तहसीलदार जगदीश रंधावा, 5 पटवारी, एक महिला समेत 13 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

नीमच एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि सीईओ धारवे के भाई ने सुबह फोन पर अपहरण की सूचना दी। तुरंत कार्रवाई करते हुए नागदा पुलिस के सहयोग से

सीईओ को छुड़वा लिया गया। आरोपियों में तहसीलदार जगदीश सिंह, पटवारी प्रमोद दास, अजय सिंह, अजय उच्छावल, पिंकी सिंह के साथ 8 अज्ञात शामिल हैं। सीईओ धारवे के बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें काले रंग की स्कार्पियो को रोकने के लिए पुलिस सड़क पर खड़ी दिखी,जैसे ही गाड़ी पास आती है, सिविल ड्रेस में खड़े पुलिसकर्मी गाड़ी को रोक लेते हैं।

बुधवार रात धारवे के घर पहुंची थी पिंकी: नीमच एसपी ने फोन पर बताया, प्रारंभिक जानकारी मिली है कि धार निवासी सीईओ धारवे की शादी की बात साल 2014 में धार की ही पिंकी सिंह से चली थी। पिंकी तहसीलदार जगदीश रंधावा की रिश्तेदार है। बुधवार रात पिंकी परिजन के साथ सीईओ धारवे के नीमच में ऑफिसर कॉलोनी स्थित आवास पहुंची।

भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को असुविधा

3 दिन से नई बिल्डिंग के सामने बह रही गटर की गंदगी, दो साल पहले 17 करोड़ में बनी थी

भोपाल (नप्र)। भोपाल स्टेशन की नई बिल्डिंग के बाहर यात्रियों को गंदगी के चलते असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि दो साल पहले करीब 17 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग के मुख्य द्वारा के सामने पिछले तीन दिनों से गटर का पानी बह रहा है। जिसके चलते बदबू और गंदगी से यात्रियों का बुरा हाल है। स्टेशन अधिकारियों के अनुसार पिछले करीब 3 दिन से लगातार यह गंदगी बनी हुई है। इस संबंध में भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों का कहना है कि समस्या का समाधान किया जा रहा है, हमारी टीमें काम कर रही हैं, जल्द ही यह दिक्कत दूर हो जाएगी।

रोजाना 25 हजार से अधिक यात्री आते हैं: प्लेटफॉर्म 1 की तरफ से आने जाने वाले यात्रियों की बात की जाए तो करीब 25 हजार से अधिक यात्री इस तरफ से आते जाते हैं। इसमें करीब 8 हजार से अधिक यात्री वृद्ध होते हैं, इसके अलावा

स्टेशन के ओवर ऑल फुटफॉल की बात की जाए तो भोपाल स्टेशन पर रोजाना करीब 45 हजार से अधिक यात्री आते हैं। वहीं यहां रोजाना करीब 250 से अधिक ट्रेनें अप डाउन में गुजरती हैं।

मोतीनगर बस्ती को तोड़ने नहीं मिल रहा फोर्स

कांग्रेसी-रहवासी जता चुके विरोध, बनना है सुभाषनगर ब्रिज की थर्ड लेन

भोपाल (नप्र)। भोपाल की मोतीनगर बस्ती को तोड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं मिल रहा है। इस कारण 2 दिन से कार्रवाई अटकी हुई है। हालांकि, इसे लेकर कांग्रेसी और रहवासी विरोध जता चुके हैं। मोतीनगर बस्ती से सुभाषनगर ब्रिज की थर्ड लेन निकलता है। बता दें कि बस्ती को हटाने के लिए रहवासियों को 4 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जानी थी। एमपी नगर एसडीएम एल.के. खरे ने बताया, कार्रवाई के लिए पुलिस बल की मांग की गई है, लेकिन दो दिन से मिल नहीं पाया है। इस वजह से कार्रवाई भी नहीं हो सकी है।

बस्ती में कुल 384 मकान: मोतीनगर बस्ती में कुल 384 मकान हैं। यहां 110 पक्की दुकानें भी हैं। इन दुकानों को हटाने से कार्रवाई की शुरुआत होगी। नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

दुल्हन को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे थे कांग्रेसी

मोतीनगर बस्ती को हटाने का विरोध भी किया जा रहा है। तीन दिन पहले कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला एक दुल्हन को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के पास पहुंच गए थे। शुक्ला ने कहा था, जिला प्रशासन की कार्रवाई के पहले मोतीनगर से कई मानवीय पहलू सामने आ रहे हैं। यदि प्रशासन मौजूद सैकड़ों परिवारों को मोहलत नहीं देता है तो उनके सामने आर्थिक संकट के अलावा नैतिक संकट भी खड़े हो रहे हैं। किसी के घर में बेटी के हाथ पीले होने हैं तो कहीं बेटे की शादी की तैयारी हो रही है। इस स्थिति में भी कार्रवाई होती है तो कई शादी भी टालनी होगी। दूसरी ओर, बच्चों की परीक्षाएं भी हैं। हालांकि, बच्चों की संख्या को लेकर प्रशासन ने सर्वे भी किया है।

संपादकीय

नवहिंदुओं की जाति !

हिंदू धर्म में अंतरित होने वालों की संख्या अन्य धर्मों में दीक्षित अथवा परिवर्तित करने वालों की तुलना में बहुत कम है। इसका बड़ा कारण हिंदू धर्म स्वीकारने के बाद भी सम्बन्धित व्यक्ति का जाति निर्धारण है। कोई भी नया हिंदू पुरानी जाति में या जाति व्यवस्थाि में जाना नहीं चाहता (खासकर अनुसूचित जाति में) क्योंकि वहां सामाजिक तौर पर ऊंच नीच का भेद बहुत स्पष्ट है। हिंदू धर्म की कई अच्छाइयों की बावजूद यह एक ऐसा रोड़ा है, जिसका हल आज तक नहीं खोजा सका है कि क्या कोई हिंदू जातिविहीन भी हो सकता है या नहीं। बहरहाल हिंदू धर्म अपनाने वालों (जिन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ घर वापसी कहता है) के सामाजिक पुनर्वास के संदर्भ में ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विचारणीय सुझाव दिया है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में आयोजित परमधर्म संसद में उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म से सनातन धर्म में वापसी करने वालों के लिए तीन अलग-अलग जातियां बनाई जाएंगी। ये जातियां क्रमशः शरणागत, भागवत और धर्मपूत कहलाएंगी। 12 साल के परीक्षण के लिए उन्हें इन्ही जातियों में रखा जाएगा। इतने दिनों सामान्य हिंदू धर्म का पालन करने पर उन्हें उनकी मूल जाति में मिल जाने की व्यवस्था दी जा सकती है। शंकराचार्यजी ने कहा कि जो लोग कभी भय, लोभ और बहकावे के कारण सनातन धर्म छोड़कर कहीं और गए थे, उन्हें अब यह अनुभव हो रहा है कि उनकी या उनके पूर्वजों की यह भूल थी। लिहाजा उन्हें अपनी भूल सुधारते हुए अपने धर्म में वापस आने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। शनिवार को सेक्टर 19 स्थित शिविर में आयोजित परमधर्म संसद में शंकराचार्य ने कहा कि घर वापसी के बाद यह प्रश्न उठता है कि वह किस जाति या वर्ण के माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि परमधर्म संसद 1008 यह व्यवस्था देती है कि उन्हें शरणागत मानकर हम उन्हें स्वीकार करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि धर्म शब्द से संबोधित होने वाला मात्र एक ही धर्म है और वह है सनातन, वैदिक, हिंदू, आर्य या परम धर्म। आजकल कुछ मत-पंथों को भी धर्म नाम से पहचान दे दी गई है, जो अनुचित है। धर्म एक ही है, दूसरा है ही नहीं तो फिर धर्मांतरण शब्द बन ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मांतरण के लिए तो एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना जरूरी होता है। स्वामीजी ने कहा कि आज पूरे विश्व में यूं तो कुल 43 सौ धर्म बताए जाते हैं पर उसमें हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, बहाई, ताओ, शिंटो प्रमुख हैं। पर मूल रूप से ये सभी धर्म नहीं कहे गए हैं। जैसे यहूदी व ईसाइयत ने स्वयं को रिलीजन, इस्लाम ने स्वयं को मजहब के रूप में पुकारा है। जब वे स्वयं ही स्वयं को धर्म कहकर नहीं पुकारते तो फिर हम उन्हें धर्म कहकर कैसे पुकार सकते हैं? यही नहीं शंकराचार्यजी ने परमधर्मादेश के जरिये यह आदेश जारी किया कि धर्म शब्द से केवल सनातन और सनातन से निकले भारतीय मूल की शाखाओं जैन, बौद्ध, सिख आदि को ही पुकारा जाए। अन्य को विशेषकर अब्राहमिक मतों को उनके मूल नाम रिलीजन, मजहब आदि से पहचाना और पुकारा जाए। शंकराचार्यजी का यह परमादेश रूपी सुझाव समग्र हिंदू समाज को कितना मान्य होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, वह वास्तविक है। लोग हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर दीक्षित हों, जो लोग गैर हिंदू धर्म में चले गए हैं, वो अपने मूल धर्म में लौटें, यह कौन नहीं चाहता। लेकिन इसके लिए हिंदू धर्म की कुप्रथा जाति को दूर अथवा संशोधित करना होगा। सर्वमान्य तरीके से यह कैसे हो, इस पर गंभीर विमर्श जरूरी है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। संप्रति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के डॉ. आंबेडकर चेयर में चेयर प्रोफेसर।

फ़िलेमॉन यैंग की भारत यात्रा और हमारी उम्मीदें

भारत का यह एक ऐतिहासिक पल है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग की भारत यात्रा शुरू हुई है। यह यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई है जब विश्व में भविष्य के लिए शिखर सम्मलेन के बाद कई तरह से परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। सतत विकास लक्ष्य-2030 के लिए पूरी पृथ्वी के राष्ट्राध्यक्ष सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिकतम इस लक्ष्य के करीब पहुँच जाएँ। यद्यपि भारत ने इस वर्ष यह नीति आयोग की रिपोर्ट से यह दावा कर चुका है कि उसने 71 प्रतिशत एसडीजी-2030 का लक्ष्य हासिल कर लिया है। महासभा के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग यह जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील है और उसे वीटो पॉवर वाली जगह मिलनी चाहिए। भारत दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में सुमार किया जाता है और इसकी आबादी ही ताकत है। इसे डेविडेंट के रूप में भारत मानता है।

भारत ने आईटी, डिजिटलाइजेशन और मानव कल्याण की योजनाओं के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक काम किया है। इसकी ग्रोथ रेट इकॉनॉमिकली बढ़ी है और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में अब भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और पड़ोसी देशों में सुधार के कारण इस क्षेत्र की जीडीपी 2025 में 5.7त्न बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएँ 2025 के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने के लिए तैयार है, जो उस समय वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब समग्र विश्व अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर रहने का अनुमान है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, मजबूत निजी खपत और निवेश के कारण भारत में इस साल 6.6प्रतिशत और 2026 में 6.8प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस दृष्टि से भी यह आज कहा जा सकता है कि भारत अपने आर्थिक पक्ष से मजबूत देश है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग, भारत सरकार के निमंत्रण पर आए हैं। वह 4 से 8 फ़रवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली, भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर बैंगलुर जाएंगे। वह भी चाहेंगे कि उनके भारत यात्रा का कुछ मतलब निकले। उनके इस यात्रा से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ-साथ भविष्य के समझौते सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत किया जाए, वह चाहते हैं। वैसे आज देखा जाए तो भारत की वैश्विक भूमिका को रेखांकित करके संयुक्त राष्ट्र व संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जो बेहतर हो सकता है, उसे मूर्त रूप दिया जा सके। फ़िलेमॉन यैंग मूलतः कैमरून गणराज्य के हैं। उन्होंने कैमरून गणराज्य के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया है। जून 2024 में, उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप सितंबर 2025 तक सुशोभित करेंगे। उनकी प्राथमिकताएं यदि देखी जाएँ तो 79वें सत्र में, अध्यक्षता संभालते हुए, यांग ने अपने वक्तव्य में विभाजित विश्व को एकजुट होने और सीमाहीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया था, जिसमें सूडान, हैती, यूक्रेन और गाजा के कठिन संघर्षों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने की भी पहल शामिल रही है। उन्होंने अपने ध्येय वाक्य विविधता में एकता, शांति की उन्नति, सतत विकास और हर जगह सभी के लिए मानव सम्मान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के तीन स्तंभ शांति एवं सुरक्षा, सतत विकास, मानवाधिकार और मानवीय सहायता को रेखांकित किया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो अभी उनके पास विजन भी है और अभी एक लंबा वक्त है जब वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए पहल कर सकते हैं। इस मुद्दे पर बैठक हेतु देशों को आमंत्रित कर सकते हैं। इस दृष्टि से अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग की यात्रा भारत के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है और भारत भी फ़िलेमॉन यैंग के लिए महत्त्वपूर्ण है। वह खुद एक स्टेट के पूर्व में नेतृत्वकर्ता के रूप में 10 वर्षों तक लगभग योगदान दिए हैं तो यह समझ सकते हैं कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र वीटो पॉवर कितना अहम् है और उसकी अहमियत वैश्विक बदलाव में क्या हो सकती है।

भारत सरकार स्वयं यह चाहती है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। विगत 10 वर्षों से अधिक समय से उसके अभूतपूर्व प्रयास में कोई कमी नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए रणनीति बहुत मजबूत है लेकिन जिन देशों का प्रतिरोध जारी है कई दसकों से कि भारत कहीं सुरक्षा परिषद में न पहुँच जाए, उसे गंभीरता से लेने की जगह भारत को ऐसे डिप्लोमेटिक विजिट पर आए अध्यक्ष से भी शिष्टाचार भेंट के दौरान अपनी बात कहने से नहीं चूकना चाहिए और यह कोशिश करनी ही होगी कि महासभा के अध्यक्ष अपनी पहल से संयुक्त राष्ट्र विस्तार के लिए ऐसी रणनीतियां बनाएं जिसमें कुछ देश वीटो देशों में सम्मिलित हों और उसमें भारत की जगह भी सुनिश्चित हो। चीन के प्रतिरोध के बावजूद यदि कुछ और देशों को सम्मिलित करने की पहल तेज होगी और उस पर वैश्विक रायसुमारी बनेगी तो भारत आज इस स्थिति में है कि उसे विश्व के देशों को शामिल करना ही होगा।

फ़िलेमॉन यैंग की यात्रा पूर्व में महासभा के अध्यक्षों की भांति की गयी यात्रा के अनुसार केवल रस्म बनकर न रह जाये बल्कि इसके कुछ परिणाम भी आए तो निश्चय ही भारत अपनी उस उपलब्धि को अर्जित कर सकेगा जिसके लिए वह वर्षों से प्रयत्न कर रहा है। हमारे प्रयास फलीभूत क्यों नहीं हुए, इसका आंकलन यदि किया जाये तो पहली बात यह समझ आती है कि भारत को अब वैश्विक चुनौतियों को रेखांकित करके लड़ने की रिश्क लेना ज़रूरी है, यह तो आज स्वीकार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, भारत की पहल और महासभा अध्यक्ष की पहल में आज अंतर समझना होगा। आज फ़िलेमॉन यैंग उस महासभा को चेयर कर रहे हैं जहाँ से बात बन सकती है, जहाँ से वह रायसुमारी के लिए देशों को एकत्रित कर अपने कार्यकाल को ऐतिहासिक बना सकते हैं, इसे चिन्हित करना ज़रूरी है।

आज भारत की यदि उपलब्धियां और उसके वैभव का यदि आंकलन किया जाए तो भारत अपनी नयी-नयी पहल से भी विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैश्विक शांति हो या गरीबी और भुखमरी के खिलाफ वैश्विक आवाज़ उठाने के लिए आगे आने में कहाँ संकट है, समझ नहीं आता। ऐसे रिश्क भारत ले तो वह खुद अनेक विघ्न पैदा करने वाले देशों को भारत के लिए सोचने हेतु मजबूर करेगा। भारत को चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग की यात्रा के दौरान ऐसे अवसर के एक-एक पल को ऐसे मानस बनाने में व्यतीत हों कि वे स्वयं भारतीय गरिमा, शक्ति, सभ्यतागत वैशिष्ट्य को विश्व के समक्ष रखें और भारत की सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए पैरोकार बनें।

उनकी ओर से यह पहल होनी ही चाहिए कि विकासशील देशों का भी सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से होना ज़रूरी है।

तीसरे विश्व युद्ध के मोहाने पर खड़े विश्व हेतु सुरक्षा परिषद में विस्तार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पाँच वीटो देश परमाणु हथियारों के भय से सशंकित हैं और सच में वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं और न कुछ रोकने के पक्ष में। ऐसे में यदि सुरक्षा परिषद में विस्तार होता है तो निश्चय ही किसी बड़े संकट से निपटने में आसानी होगी। फ़िलेमॉन यैंग की इस यात्रा से निःसंदेह कुछ रचनात्मक हो सकता है लेकिन यह सब तब होगा जब भारत और फ़िलेमॉन यैंग के बीच विश्व के बदलाव की इच्छाशक्ति होगी।

म सभी इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि किसी भी व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करने में उसकी आयु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, और जटिल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता उम्र के साथ बदलती रहती है। आयु का आरोह व्यक्ति को ऊर्जावान, अनुभवी और आत्मविश्वासी बनाता है, जिससे वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में न केवल कुशलता से कार्य करता है बल्कि प्रभावशाली निर्णय भी ले पाता है। दूसरी ओर, उम्र का अवरोह कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, शरीर को थकान का अनुभव होने लगता है, निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है और व्यक्ति का प्रदर्शन धीरे-धीरे घटने लगता है।

यही कारण है कि अधिकांश व्यवसायों में कार्य करने की अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। सरकारी नौकरियों में, चाहे वह प्रशासनिक सेवाएं हों, सुरक्षा बल हों, शिक्षण संस्थान हों या अन्य कोई सेवा, सेवानिवृत्ति की आयु आमतौर पर 58 से 62 वर्ष के बीच निर्धारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की घटती शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे विश्राम और नए योग्य व्यक्तियों को अवसर दिया जाए। लेकिन जब बात हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की आती है, तो यह नियम पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाता है।

यह अत्यंत आश्चर्यजनक और विडंबनापूर्ण है कि जो लोग जनता के सेवक कहलाते हैं, जो लोकतंत्र के कर्णधार माने जाते हैं, वे स्वयं को कार्यक्षमता के इस मापदंड से पूरी तरह मुक्त कर लेते हैं। हमारे देश में अधिकांश नेता 60 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी सक्रिय राजनीति में बने रहते हैं। यहाँ तक कि कई शीर्ष पदों पर आसीन राजनेता 70, 80 या 90 वर्ष की अवस्था में भी कुर्सी कुर्सी की रट लगाए रहते हैं। यह विचारणीय प्रश्न है कि यदि 60 वर्ष के बाद एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है क्योंकि उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आ जाती है, तो वही नियम हमारे नेताओं पर क्यों लागू नहीं होता? क्या वे किसी विशेष मिट्टी के बने होते हैं जिन पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता? क्या उनकी कार्यक्षमता बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती ही जाती है? नेताओं के लिए सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें राजनीति की उस वास्तविकता को समझना होगा जो इसे अन्य सेवाओं से अलग बनाती है। राजनीति को एक सेवा की बजाय एक व्यवसाय बना दिया गया है, जहाँ आने के बाद व्यक्ति आजीवन उसी में बना रहना चाहता है। अधिकांश नेता राजनीति को एक ऐसी कुर्सी समझते हैं, जिस पर बैठने के बाद वे कभी उठना नहीं चाहते। उनके लिए यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा होती है, जो तब तक जारी रहती है जब तक प्रकृति उन्हें स्वयं सेवानिवृत्त नहीं कर देती।

इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण इन्हें मिलने वाली असीमित शक्तियां और विशेषाधिकार है। जनप्रतिनिधियों को जो अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वे किसी अन्य व्यवसाय में उपलब्ध नहीं होते। उनकी निर्णय लेने की शक्ति, सरकारी संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति उन्हें पद से चिपके रहने के लिए प्रेरित करती है।

यह एक कटु सत्य है कि हमारे सांसद और विधायक जब चाहें, बिना किसी विरोध के, अपने वेतन और भत्ते बढ़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी बाहरी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह और भत्तों के लिए सरकार की कृपा पर निर्भर होते हैं, वहीं नेता स्वयं ही अपने वेतन-भत्ते तय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही वह दूसरा कारण है, जिसके लिए वे कभी अपनी मर्जी से राजनीति छोड़ना नहीं चाहते।

तीसरे, भारतीय राजनीति में वंशवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। अधिकांश वरिष्ठ नेता अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में स्थापित करने के लिए लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। वे तब तक पद नहीं छोड़ते जब तक उनका उत्तराधिकारी तैयार नहीं हो जाता।

चौथा कारण यह है कि राजनीति में आम धारणा यह है कि यहां अनुभव सबसे बड़ी योग्यता है। हालांकि यह सच है कि अनुभव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि केवल उम्रदराज नेताओं को ही राजनीति में रहने दिया जाए। युवा नेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बजाय, अनुभवी नेता राजनीति को अपनी निजी संपत्ति बना लेते हैं।

राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र तक चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। यदि अन्य व्यवसायों में अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की जा सकती है, तो राजनीति में क्यों नहीं?

हम अक्सर देखते हैं कि बड़े-बड़े नेता अत्यधिक उम्र होने के बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर बने रहते हैं। वे कानून बनाते हैं, देश की नीतियों को तय करते हैं और जनता के भविष्य का निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या वे स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम होते हैं कि वे यह कार्य प्रभावी रूप से कर सकें? अक्सर ऐसे नेताओं की कार्यशैली सुस्त हो जाती है, वे जनता से संवाद स्थापित करने में असमर्थ हो जाते हैं और कई बार तो उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी ठीक से बोलने में कठिनाई होती है। क्या ऐसे नेता देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं? यदि एक सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र के बाद कार्य करने में अक्षम माना जाता है, तो एक 80 वर्षीय नेता कैसे पूर्ण ऊर्जा और क्षमता के साथ राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है? क्या नेताओं के लिए देश महत्त्वपूर्ण नहीं होता?

अब समय आ गया है कि राजनीति में भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। यदि सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्ति की उम्र होती है, तो राजनीति में भी यह नियम लागू होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा होने से युवा और योग्य नेताओं को आगे आने का अवसर मिलेगा, जिससे नई सोच और ऊर्जा राजनीति में आएगी।

जब राजनीतिक पदों पर अधिक ऊर्जावान और सक्षम लोग होंगे, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। वरिष्ठ नेता जब तक राजनीति में बने रहते हैं, तब तक वे अपने परिवार के सदस्यों के लिए रास्ता तैयार करते रहते हैं। यदि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित होगी, तो वंशवाद पर कुछ हद तक नियंत्रण लग सकता है। जब अनुभवी लेकिन अति वृद्ध नेताओं की जगह युवा, जोश से भरे और कुशल नेता आएंगे, तो देश का विकास अधिक तेजी से होगा।

राजनीति कोई नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने का माध्यम है। लेकिन इसे व्यवसाय बना लेने की प्रवृत्ति के कारण ही अधिकतर नेता आजीवन पद पर बने रहने की कोशिश करते हैं। कार्यक्षमता और आयु का संबंध अटूट है और इसे राजनीति में भी मान्यता मिलनी चाहिए। यदि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जजों, सेना और अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसा कोई नियम क्यों नहीं?

यदि हम सचमुच लोकतंत्र को सशक्त और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा और राजनीति में भी एक अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करनी होगी। इससे न केवल कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।

आर्थिकी

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे पाएगी एकीकृत पेंशन योजना?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की जगह एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है। यह टी के सुझावों पर आधारित है। सिफारिशें 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी। यूपीएस के प्रस्ताव के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लाभों को एक साथ जोड़ा जाएगा। भारत में सेवानिवृत्ति योजना के लिए इस दूरदर्शी दृष्टिकोण का लक्ष्य सभी योग्य कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और दीर्घकालिक पेंशन प्रणाली है। यह सरकारी कर्मचारियों की स्वतंत्रता और पसंद को संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत इस विकल्प का चयन करते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं, वे यूपीएस के अधीन हैं। वर्तमान और भावी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उनके पास वर्तमान एनपीएस योजना के साथ बने रहने या यूपीएस में स्विच करने का विकल्प है।

यूपीएस में स्विच करना एक बार तय हो जाने के बाद अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। यूपीएस को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी किए गए विनियमों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। 1 अप्रैल, 2025 वह तारीख है जिस दिन एकीकृत पेंशन योजना लागू होगी। यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी दी जाती है जो सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए उनके औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होती है। 10 से 25 साल तक की सेवा अवधि के लिए पेंशन आनुपातिक होगी। कम से कम 25 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी पूरी सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र होंगे। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु-पूर्व पेंशन के 60 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाएगी। जिन कर्मचारियों ने कम से कम दस साल तक काम किया है, उन्हें सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10, 000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सेवानिवृत्त लोगों के लिए, यह एक सुरक्षा जाल की गारंटी देता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 25 साल तक काम किया है, उन्हें पेंशन की गारंटी दी जाती है। यह सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए उनके औसत आधार वेतन का आधा हिस्सा लेकर निर्धारित किया जाता है। यूपीएस सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित पेंशन को मुद्रास्फीति के साथ अनुक्रमित करता है। महंगाई राहत के रूप में, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित है और सहायता श्रमिकों के बराबर है। मासिक वेतन का दसवां हिस्सा और महंगाई भत्ता प्रत्येक पूर्ण छह महीने की सेवा अवधि के लिए ग्रेच्युटी में जोड़ा जाता है। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन का दस प्रतिशत अभी भी योगदान दिया जाएगा। सरकार वर्तमान 14 प्रतिशत के बजाय 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी। यह गारंटी देता है कि श्रमिकों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव नहीं डाला जाएगा। जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक पहुँचते हैं, तो यूपीएस गारंटीकृत भुगतान प्रदान करता है।

सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में, यूपीएस एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा, जब तक कि उन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली हो। जिन श्रमिकों ने दस साल से अधिक लेकिन पच्चीस साल से कम समय तक काम किया है, वे आनुपातिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। दस साल या उससे ज़्यादा की अर्हक सेवा के बाद, कर्मचारियों को हर महीने 10, 000 रुपये का न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। यह भुगतान उस दिन से शुरू होगा, जिस दिन अगर वे काम करना जारी रखते, तो वे 25 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच जाते। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान धारक की मृत्यु की स्थिति में धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60 प्रतिशत पारिवारिक भुगतान मिलेगा। गारंटीकृत भुगतान और पारिवारिक भुगतान भी महंगाई राहत के लिए पात्र होंगे, जिसका निर्धारण उसी तरह किया जाएगा।

सेवारत कर्मचारियों के लिए, महंगाई राहत की गणना महंगाई भत्ते के समान ही की जाएगी। यूपीएस या गारंटीकृत भुगतान उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा जब कोई कर्मचारी इस्तीफा दे देता है या उसे सेवा से हटा दिया जाता है। पिछली पेंशन योजना के विपरीत, यूपीएस एक अंशदायी योजना है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार, जो कि नियोक्ता है, 18 प्रतिशत का योगदान करेगी। वह कोष, जिसे मुख्य रूप से सरकारी ऋण में निवेश किया जाता है, अंततः बाज़ार के रिटर्न के आधार पर भुगतान का निर्धारण करेगा। यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध दो विकल्प हैं। यूपीएस के विपरीत, एनपीएस बाज़ार से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित लाभों के सम्बंध में यूपीएस और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के बीच समानताएँ हैं। हालांकि, इसे वित्त पोषित करने का तरीक़ा बहुत अलग है।

यूपीएस को प्रत्येक वर्ष बजट से अपना सारा वित्त पोषण प्राप्त होता है, ओपीएस के विपरीत, जो कि पे-एज-यू-गो कार्यक्रम था कर्मचारी एनपीएस के माध्यम से सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण कर सकते हैं, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है जिसे पहली बार 2004 में लागू किया गया था। जो लोग अधिक गारंटी वाली पेंशन की तलाश में हैं, उनके लिए यूपीएस एक विकल्प प्रदान करता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

राजेंद्र बज

लेखक व्यंग्यकार हैं।

अगली पंक्तियों पर मैं, आपकी दाद चाहूंगा

वैसे तो मैं किसी कवि की 'वैचारिक पहुंच' तक नहीं पहुंच पाता, कविता के भावार्थ को समझना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। लेकिन कवि सम्मेलन में शिरकत अवश्य करता हूं। दरअसल मुझे चुटकुले सुनना बहुत रास आता है। और कवि सम्मेलन ही ऐसा ठिया है जहां थोकबंद चुटकुलों का श्रवण किया जा सकता है। वरना तो आजकल आदमी ही इस कदर चुटकुला बना हुआ है कि क्या खाएं और क्या पिएं, हंसे और मुस्कुराए भी ... तो आखिर किस बात पर ! एक तो वैसे ही आम आदमी के हंसने और मुस्कुराने की वजह दुर्लभ हो चली है। ऐसे में यदि कवि सम्मेलन में गहरी बात कह दी जाए, तो आम आदमी के लिए तो यह मामला दुबले और दो आषाढ़ जैसा हो जाएगा।

कवि सम्मेलन में कुछ कवि कविता भी सुना दिया करते है। जिसे चुटकुले सुनने के लोभ में मुझे भी सुनना पड़ता है। खैर, जब कभी कोई कवि कविता सुनाने के मूड में होता है, भूमिका अवश्य बांधता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यह कहना नहीं भूलता कि 'अगली पंक्तियों पर मैं आपकी दाद चाहूंगा।' इन पंक्तियों को सुनकर श्रोता कुछ चौकन्ने हो जाते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक अगली पंक्तियों का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगली पंक्तियों में जरूर कोई खास बात है। दरअसल हर आदमी अपने आप में इतना खोया हुआ रहता है कि कभी-कभी गहरी से गहरी बात भी उसके पल्ले नहीं पड़ती। साफ़ कहे तो सीधी सिर से ऊपर निकल जाती है। इस बात का कवि लोग बखूबी ध्यान रखते हैं। खैर।

अब मैं ठहरा आग्रह का कच्चा, तत्काल प्रभाव से अपना मन बना लेता हूं कि चाहे कविता की गहराई समझ में आए या नहीं आए, लेकिन मुझे ताली अवश्य बजाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा मैं ही हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कवि सम्मेलन में कवि के कहे का मान रख लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को ताली बजाते हुए देखने पर खुद भी ताली बजा दिया करते हैं। इसके चलते कवि को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कविता वाचन के दौरान अपनी बिरादरी के लोगों को पलट-पलट कर देखता है। नजर मिलते ही बिरादरी के लोग भी (शरमा शरमी) 'वाह वाह' का उद्घोष कर दिया करते हैं। इस मामले में एक दूसरे को एक दूसरे का हिसाब किताब सही-सही रखना होता है। वैसे भी एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अब मैं तो हर कवि की अगली पंक्तियों पर ताली बजा दिया करता हूं। इसके चलते कविता की गहराई में गोते लगाने वालों की श्रेणी में मैं भी शुमार हो जाता हूं। वैसे यह शोध का विषय है कि आमतौर पर जहां कहीं छोटे बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, वहां उपस्थित तमाम श्रोताओं में से मेरी सोच से इत्तेफाक रखने वाले कितने लोग होंगे । वह तो भला हो कवि सम्मेलन के आयोजकों का, और भला हो कविता के नाम पर चुटकुले सुनाने वालों का, और उनका भी भला हो जो कवि सम्मेलन के लिए चंदा देते हैं। थोड़ा बहुत उनका भी भला हो जो वास्तव में कवि सम्मेलन में कविता पाठ ही करते हैं। जिसके चलते कवि सम्मेलन की परंपरा आज भी जिंदा है।

वैसे कहा जाता है कि चोट खाया आदमी कविता में डुबकी लगाकर मदहोशी के आलम में आ जाता है। चतुर सुजान कहते हैं कि कविता मन के दर्द और पीड़ा को स्वर देती है। जिसके चलते कैसी भी चोट खाया घायल आदमी कविता के मरहम से अपने गम को गलत कर लेता है। कभी-कभी सोचता हूं कि गम गलत करना आजकल काफी महंगा सौदा हो गया है। इसलिए कवि सम्मेलन में जाकर अपने रंजो गम भूल जाता हूं। हंसने मुस्कुराने और खिलखिलाने की मुझे वजह मिल जाती है। हालांकि आजकल के दौर में कवि सम्मेलन कम हो चले हैं। जिसके चलते मुद्दत गुजर गई , मैं कभी हंस नहीं पाया। इसलिए जब कहीं मौका मिलता है, कवि सम्मेलन में शिरकत करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता। चाहे मुझे गंभीर कविता पर जबरदस्ती ताली बजाना पड़े, लेकिन चुटकुलों की आस में ताली बजाना घाटे का सौदा नहीं लगता।

जब कभी किसी कवि सम्मेलन में चले जाता हूं, चुटकुले पर चुटकुले सुनते हुए अंतर्मन में असीम आनंद की दिव्य अनुभूति हुआ करती है। और कवि के कहने पर मैं जमकर ताली बजा दिया करता हूं। अब ऐसा है कि जमाने में जमाने भर के संतापों से मुक्ति का मौका कम ही मिला करता है। इसलिए किसी भी कवि सम्मेलन को छोड़ना नहीं चाहता। कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और कहीं कोई चुटकुला देखने सुनने या पढ़ने मे आता है, लगभग सारे के सारे बहुत घिसे पिटे लगते हैं। एक कवि सम्मेलन ही ऐसा है जहां कुछ नया सुनने को मिल जाता है।

दृष्टिकोण

आर बी. त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

अध्यात्म और सनातन के चरमोत्कर्ष का दौर और दुर्घटना

महाकुंभ में वसंत पंचमी पर्व पर संपन्न अमृत स्नान बिना किसी अप्रिय घटना के होने पर सभी ने राहत की सांस ली है। इसके पूर्व हुई दुर्घटना ने कई अनुत्तरित सवाल खड़े किये हैं। सरकार ने आनन फानन में जांच बैठाई, जांच शुरू भी हो गई, शायद कुछ जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हो और धीरे धीरे इस घटना के सबक को भुला भी दिया जायेगा। यही सब होता रहा है। जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके दु:ख का कोई पारावार नहीं है। कुछ लाख रुपयों की मदद से उनके जख्मों को भरा नहीं जा सकता। सवाल यह भी है कि जैसे प्रबंध वसंत पंचमी के स्नान के मौके पर किये गये वे पहले क्यों नहीं किये गये? चूक आखिर हुई कहां?

प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई मौतों पर मृतकों के परिजन सहित सभी लोग स्तब्ध हैं। संसद तक इसकी अनुगूंज सुनाई दी है। घटना पर किसने क्या कहा, सियासत कितनी हुई इस पर फिलहाल नहीं जाकर इस घटना को लेकर क्या सबक लिया और भविष्य के लिये क्या रणनीति होना चाहिये यह विचारणीय है।

एक ऐसे समय जब बीते कुछ वर्षों में हमारे यहां अध्यात्मिकता और सनातन की बात और प्रसार अपने चरम पर है तब प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतें कई नये सवाल तो खड़े करती है। इस दौरान ना केवल महाकुंभ में बल्कि अयोध्या से लेकर हरिद्वार, वाराणसी, चित्रकूट से लेकर उज्जैन, ओंकारेश्वर तथा अन्य पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही स्वाभाविक ही बड़ी तेजी से बड़ गई।इन जगहों पर श्रद्धालुजन को आसानी दर्शन स्नान का लाभ मिल जाना उस अदृश्य शक्ति की कृपा कही जाना चाहिये।

महाकुंभ में वसंत पंचमी पर्व पर संपन्न अमृत स्नान बिना किसी अप्रिय घटना के होने पर सभी ने राहत की सांस ली है। इसके पूर्व हुई दुर्घटना ने कई अनुत्तरित सवाल खड़े किये हैं। सरकार ने आनन फानन में जांच बैठाई, जांच शुरू भी हो गई, शायद कुछ जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हो और धीरे धीरे इस घटना के सबक को भुला भी दिया जायेगा। यही सब होता रहा है। जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके दुःख का कोई पारावार नहीं है। कुछ लाख रुपयों की मदद से उनके जख्मों को भरा नहीं जा सकता। सवाल यह भी है कि जैसे प्रबंध वसंत पंचमी के स्नान के मौके पर किये गये वे पहले क्यों नहीं किये गये? चूक आखिर हुई कहां?

बीते दिनों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उनसे तो यही प्रतीत होता है कि जिम्मेदारों ने अपनी भूमिका का निर्वाह मुस्तैदी और सतर्कता बरतकर किया होता तो घटना को रोका जा सकता था। जब आप नदी के जल से लेकर जमीन, स्नान घाट से लेकर आकाश तक सुरक्षा के प्रबंध तथा निगरानी का दावा करते हैं तो फिर लोगों की जान पर कैसे बन जाती है?

सवाल यह भी है कि महाकुंभ के आयोजन का जिस तरह अति प्रचार हुआ उससे स्वाभाविक ही लाखों-करोड़ों की भीड़ उमड़ने की संभावना थी, इसे लेकर कितनी प्लानिंग की गई और कितना अमल किया गया। क्या देश क्या विदेश, शहरों कस्बों तथा सुदूर गांव देहातों से श्रद्धालुजन एक थैले में जरूरी सामान के साथ बड़े भरोसे के साथ चले आते हैं। इस बात की परवाह किये बिना कि कड़कड़ाती सर्दियों में वे कैसे कहां ठहरेंगे और रेलवे स्टेशन, बस अड्डों से गंतव्य तक कैसे पहुंचकर सुरक्षित लौटेंगे। सो, बड़ी तादाद में श्रद्धालुजन, महिलाएं, बुजुर्ग और यहां तक कि छोटे बच्चों को साथ लिये

परिवारों के समूह महाकुंभ पहुंच गये तथा यह सिलसिला जारी है।

अमृत स्नान के संकल्प की चाह ऐसी कि खुले आसमान तले रात बिताने और देर रात या तड़के स्नान के लिये घाटों की ओर निकल पड़ने में उन्हें कोई गुरेज नहीं। बगैर इस बात का इंतजार किये कि महाकुंभ में पर्वों पर स्नान सबसे पहले साधु संतों,अखाड़ों द्वारा किये जाने की परम्परा है।उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और अपार जनसमूह से निकलकर आने वाले लोगों ने जो कुछ बयां किया वह कथित तौर पर बदइंतजामी की पराकाष्ठा को ही उजागर करता प्रतीत होता है। अपनों को खोने वाले लोगों का रोना बिलखना और विलाप किसी को भी दृवित कर सकता है।

दरअसल चाहे कोई कुछ भी कहे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि तीर्थाटन जैसा पवित्र कार्य तथा उद्देश्य भी अब धीरे- धीरे धार्मिक पर्यटन का स्वरूप लेता जा रहा है। नतीजतन ज्यादातर नव धनाड्य वर्ग अपने परिवारों को लेकर बड़ी-बड़ी लग्जरी गाड़ियों में बेखौफ तीर्थ स्थलों के लिये निकल पड़ते हैं। बिना यह सोचे समझे कि लंबे रास्तों पर अनायास कोई दुर्घटना हुई या वाहनों का जाम लगा या विपरीत मौसम हो गया तो क्या करेंगे। महाकुंभ की दुर्घटना के बाद जिस तरह श्रद्धालुओं को बीच रास्ते कहीं पर भी रोका गया और इससे लगे लंबे-लंबे जाम की तस्वीरें डराती भी हैं और भविष्य के लिये सीख भी देती है। लेकिन चाहे श्रद्धालुजन हो या जिम्मेदार लोग सबक लेते कहां है। हमने ना तो उत्तराखंड की बरसों पहले घटी भयावह त्रासदी से सबक लिया ना ही उत्तर प्रदेश के हाथरस के समीप कथित धार्मिक समागम में भगदड़ से हुई मौतों से कुछ सीख ली। ना ही उज्जैन में महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर तथा सीहोर के समीप कुण्डेश्वर या फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत में धार्मिक समागम के दौरान मंच टूटने की घटना या अन्य घटनाओं से कोई सबक लिया। ईश्वर ने हमें भूलने की बड़ी शक्ति जो दी है?

आने वाले समय में नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होना है। सो प्रयागराज राज की दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में इन जगहों और इसी माह आने वाले पवित्र महा शिवरात्रि के पर्व पर विभिन्न मंदिरों तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुजन सुरक्षित रूप से सुगमता से दर्शन, पूजा-पाठ कर सकें इसके लिये अभी से कार्य योजना तैयार कर बेहतर इंतजाम किये जाना आज की जरूरत है।

नभ में फहरते तीर्थ पुरोहितों के ध्वज-निशान

प्रयाग कुम्भ

– प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शिक्षक एवं स्तंभकार हैं।

जब मैं कल्पवास करने पहुंचा तो देखा कर दंग रह गया कि तम्बुओं का व्यवस्थित नगर बसा हुआ है। प्रत्येक पंडा को गंगा की रेती पर कुछ भूभाग आवंटित किया गया है जिसे टीन की चादरों की चारदीवारी से सुरक्षित कर उसके अंदर तम्बू लगाए गये हैं। इस स्थान को बाड़ा या छावनी भी कहा जाता है। प्रत्येक बाड़े में पानी की आपूर्ति हेतु नल एवं टोंटी लगे हैं, प्रत्येक तम्बू में प्रकाश हेतु विद्युत तार एवं बल्ब का प्रबंध है। मांग पर तम्बू के बाहर शौचालय भी स्थापित कर दिया जाता है। बाड़े के बाहर सैकड़ों सार्वजनिक शौचालय हैं और खाली मैदान भी पड़ा है। मैंने अपने तम्बू के पीछे एक शौचालय और नल स्थापित करवाया है।

लेख का आरम्भ मैं एक श्लोक की पंक्ति से करता हूं- मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वजः, अर्थात् जिनके ध्वज में पक्षी गरुण अंकित है, ऐसे भगवान विष्णु हमारा मंगल करें। प्रत्येक देवी-देवता के वाहन में लगे ध्वज में कोई न कोई प्रतीक चिह्न अवश्य अंकित है जो आध्यात्मिक अर्थों को सहेजे हुए है। ऐसे ही महाभारतकालीन योद्धाओं के रथों में जो ध्वज लहरा रहे थे, उनमें प्रतीक चिह्न अंकित थे ताकि योद्धा दूर से पहचाने जा सकें।राजा-महाराजाओं के राज्य में भी प्रतीक चिह्न हुआ करता था जिसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में ससम्मान प्रदर्शित किया जाता था और राजा के किसी अभियान में जाने पर राजचिह्न अंकित ध्वज सम्मानपूर्वक लेकर अश्वारोही और पैदल सैनिक आगे-आगे चलते थे। वर्तमान युग में भी देशों के अपने ध्वज होते हैं जो एक रंग के या रंग-बिरंगे होते हैं और उनमें कोई चिह्न छपा होता है। शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, स्कूल, कालेज एवं विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं, प्रदेशीय सरकारों के प्रतीक चिह्न/लोगो होते हैं। ये प्रतीक चिह्न सम्बंधित संस्थान की दृष्टि, विचार एवं उद्देश्य तथा पहचान को प्रकट करते हैं। अपने प्रतीक चिह्न के आदर्श को बनाये रखने के लिए नागरिक या कार्यालयों के कर्मचारी सदाचरण करते हैं।

पाठकों की जानकारी के लिए मैं महाभारतकालीन योद्धाओं के ध्वज और उनमें अंकित चिह्नों के बारे में लिखना उचित समझता हूं। कौरव पक्ष के वयोवृद्ध योद्धा देवव्रत भीष्म के रथ पर फहरते विशाल ध्वज पर ताड़ का ऊंचा वृक्ष और 5 तारे अंकित थे, गुरु द्रोणाचार्य के ध्वज में वेदिका, एक कटोरा और धनुष-बाण चित्रित थे। कौरव कुलगुरु कृपाचार्य के ध्वज पर गाय-बैल या सांड का चित्र था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के स्वर्ण सज्जित ध्वज पर उगते सूर्य की आभा सहेजे शेर की पूंछ शोभायमान थी तो हल अंकित ध्वज मद्र नरेश के रथ पर फहर रहा था। जयद्रथ की ध्वजा पर रजत वराह तो युवराज दुर्योधन के ध्वज पर फन पर जड़ित हीरायुक्त सर्प का चिह्न था। दानवीर कर्ण के रथ पर श्वेत शंख और सोने की बनी रस्सी थी। पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के ध्वज पर नक्षत्रयुक्त चंद्रमा, भीम के ध्वज पर चांदी से बना विशाल शेर बना था। सुंदर नकुल का झंडा निशान था स्वर्ण पीठ वाला हिरन और सहदेव का ध्वज चिह्न था चांदी का हंस। अर्जुन के कपिध्वज पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे, अभिमन्यु के ध्वज की पृष्ठभूमि में पीले पत्तों वाला वृक्ष बना था। वीर घटोत्कच के झंडे पर गिद्ध अंकित था तो बलराम के झंडे पर ताल वृक्ष। ऐसे ही अन्यान्य योद्धाओं के ध्वज पर विशेष चिह्न अंकित थे जो उनकी पहचान और विशिष्टता को प्रदर्शित करने वाले थे।

पाठक सोच रहे होंगे कि मैं ध्वज और उनमें अंकित चिह्नों की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल आजकल मैं महाकुंभ प्रयागराज में कल्पवास कर रहा हूं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से आरंभ हुआ कल्पवास माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को पूर्ण होगा। कल्पवास की

मास पर्यंत अवधि हेतु रहने आदि का प्रबंध प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित करते हैं, जिन्हें सामान्यतः पंडा कहा जाता है। ये पंडे ब्राह्मण वर्ग से हैं और सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तीर्थयात्रियों को कल्पवास करने हेतु आवास आदि की व्यवस्था करते आयें हैं।? तीर्थयात्रियों द्वारा गंगा स्नान पश्चात् पूजन संकल्प और अन्य धार्मिक कर्मकांड करवाने के बाद श्रद्धापूर्वक प्राप्त दान-दक्षिणा ही पंडों की आय का एकमात्र स्रोत है। कुम्भ के आयोजन और वार्षिक माघ मेले के बाद अन्य महीनों में भी ये पंडे दूर-दूर से आने वाले अपने यजमानों के रहने एवं भोजन आदि का समुचित प्रबंध करते हैं। प्रत्येक पंड़े का देश भर में एक या कुछ जनपद निश्चित हैं और उन जनपदों के निवासी यजमान अपने सभी धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्मकांड केवल अपने पंडा से ही करवाते हैं। प्रत्येक पंड़ा का गंगा घाट पर एक स्थान निश्चित है जिसे उनकी भाषा में तखत कहा जाता है।? जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक पंडे के तखत का एक रजिस्टर्ड नम्बर होता है, जिसे वे पोस्टर या बैनर पर अंकित करवाते हैं। यह तखत नम्बर प्रशासन द्वारा उन्हें आवंटित किया जाता है। जब मेरे मन में कल्पवास करने की प्रेरणा-इच्छा हुई तो मैंने अपने गांव बल्लान जिला बांदा के पंडा माधौप्रसाद पंडा के वंशज आशीष पंडा जी से सम्पर्क किया और मेरा पूरा प्रबंध हो गया।

जब मैं कल्पवास करने पहुंचा तो देखा कर दंग रह गया कि तम्बुओं का व्यवस्थित नगर बसा हुआ है। प्रत्येक पंडा को गंगा की रेती पर कुछ भूभाग आवंटित किया गया है जिसे टीन की चादरों की चारदीवारी से सुरक्षित कर उसके अंदर तम्बू लगाए गये हैं।? इस स्थान को बाड़ा या छावनी भी कहा जाता है। प्रत्येक बाड़े में पानी की आपूर्ति हेतु नल एवं टोंटी लगे हैं, प्रत्येक तम्बू में प्रकाश हेतु विद्युत तार एवं बल्ब का प्रबंध है। मांग पर तम्बू के बाहर शौचालय भी स्थापित कर दिया जाता है। बाड़े के बाहर सैकड़ों सार्वजनिक शौचालय हैं और खाली मैदान भी पड़ा है। मैंने अपने तम्बू के पीछे एक शौचालय और नल स्थापित करवाया है।

एक सुबह मैंने देखा कि इस तम्बू नगरी के नील गगन में सैंकड़ों ध्वज-पताका फहर रहे हैं जिन पर तरह-तरह के चिह्न अंकित हैं। इन झंडों पर बने चित्र आमजन के दैनिक प्रयोग की वस्तुओं से जुड़े हैं, यथा - नारियल, मछली, पीतल की कड़ाही, लोटा, घंटा, चांदी का नारियल, जटा वाला नारियल, निहाई और हथौड़ा, चौखुटा क्रास, दो लौकी, हाथ का पंजा, सूरज, लालटेन और ढाल, टेढ़ी नीम, बारहखम्भा, चरण पादुका, बरगद का पेड़, डलिया, पांच राइफल, ऊंट, घोड़ा, हाथी, रेडियों, पांच सैनिक, दीपक, पान का पत्ता सहित लाल, हरे, नीले आयताकार सादे झंडे। किसी-किसी बाड़े में झंडा निशान के साथ ही झंडे में अंकित वस्तु भी एक ऊंचे बांस पर टांग दी गयी है। इतनी तरह के झंडा निशान क्यों, मैंने अपनी जिज्ञासा लालटून का झंडा वाले आशीष पंडा के सम्मुख रखी।

वे कहते हैं कि यह सदियों से पंडों की पहचान का आधार रहे हैं। जब जनता-यजमान पढ़े-लिखे नहीं होते थे तब वे संगम क्षेत्र में अपने तीर्थ पुरोहित पंडा को आसानी से पहचान सकें, इसके लिए झंडा और निशान बनाए गये थे। यह सुन मैं आश्चर्यचकित था कि तभी मैंने एक प्रश्न प्रकट किया कि ये झंडा निशान का निर्धारण कौन करता है। पास ही बैठे श्याम पंडा के पुत्र गौतम बोले कि पंडों की अपनी एक समिति है प्रयागवाल समिति। यही समिति झंडा निशान तय करती है। वास्तव में, पंडों के झंडों की यह दुनिया बहुत विशाल, रोचक, प्रेरक और परम्परा को सहेजे यजमानों के हित-कल्याण हेतु अहर्निश साधनारत है।

माफी मांगो पर नाक का तो ख्याल रखो

कटाक्ष

सुरेश उपाध्याय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

> क्षमा विरस्य भूषणम' व 'क्षमा बडन को चाहिए' जैसी उक्तिया क्षमा के महत्व को प्रतिपादित करती है. क्षमा को वीर का आभूषण व बडप्पन का प्रतीक मानने का भाव इनमें समाहित है. पर्वो की परम्परा में 'क्षमा पर्व' का हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व है, इस पर सहज भाव से जाने-अनजाने में हुई गलतियो के लिए व्यक्तिगत व सामूहिक रुप से क्षमा पार्थना व आकांक्षा की जाती है।

किसी से कभी कोई भूल/गलती/त्रुटी होती है तो 'माफ करना' / 'क्षमा करना' 'सोरी कहना' सामान्य शिष्टचार के तौर पर प्रयोग किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि माफी मांगने से आत्मग्लानी का क्षमन होता है तथा मन का बोझ हल्का होता है. इससे दूसरे पक्ष को भी संतुष्टि होती है कि चलो मामला रफा दफा करो. वैसे भूल होना और भूल करना में बडा फर्क होता है. भूल करने वाला आसानी से माफी नही मांगता है, वह किसी दबाव, बडे नुकसान व प्रतिकूल परिस्थिति में ही विवश होकर ऐसा करता है. माफी मांगना उसे अपमानकारी लगता है, उसके ईगो को हर्ट (अहंकार को ठेस) करता है. आवेग व आवेश में कही गई बातो का बाद में यदि पछतावा हो और पश्चाताप में माफी की प्रार्थना हो तो यह एक ऐसा विकल्प है जो दोनो पक्षो को राहत प्रदान करता है।

सामान्य जीवन में माफी मांगने व माफ करने की प्रवृत्ति संकुचित होती दिखाई देती है जबकि माफी के शब्दो (ज्यादातर - सोरी) का औपचारिक प्रयोग बहुतायत में हो रहा है. राजनीति के कोलाहल में बयानो को लेकर 'माफी मांगो ङ्क माफी मांगो' के स्वर आए दिन सुनाई देते हैं. एक तरफ से किसी कृत्य या वक्तव्य के लिए 'माफी मांगो' की आवाज आई नही कि दूसरे तरफ से इसके जवाब में कोई कृत्य या वक्तव्य ढूंढ लिया जाता है और इधर से भी 'माफी मांगो' के नारे गुंजने लगते हैं. इनकी सफाई में वक्तव्य का गलत अर्थ, संदर्भ से हटकर आशय, त्रुटीपूर्ण व मनमानी व्याख्या से लेकर आडियो / विडियो से छेडछाड तक की बाते सामने आती है. जीभ का फिसलना (स्लीप आफ टंग) भी कई मर्तबा माफी मांगने की जड से जूडा रहता है लेकिन इसको स्वीकारना भी हिम्मत का काम है. तकनीक के उपयोग व दुरुपयोग के युग में सामान्यजन किसी निष्कर्ष पर नही पन्हुच पाता है लेकिन अनुयायी व समर्थक अपने अपने पक्षो के 'माफी मांगो' के नारो को गुंजायमान रखते हैं. यह प्रक्रिया अगले किसी अवसर तक जारी रखी जा सकती है. कभी कभी माफी की मांग समय का अतिक्रमण करते हुए इतिहास की अतल गहराईयो तक पन्हुच जाती है और पूर्वजो तक को वर्तमान परिदृष्य में खींच लाती है. माफीवीर, जयचंद, मीर जाफर आदि इत्यादी पात्र इतिहास के पन्नो से निकल कर वर्तमान में रमण करने लगते हैं. इतिहास की गलती के लिए कौन किससे माफी मांगेगा?, अलबत्ता इतिहास की गलतियो से सबक सीखा जा सकता है, उसके लिए तो कोई तैय्यार दिखता नही है. वैसे ऐतिहासिक गलतियो के लिए माफी मांगने के उदाहरण भी मौजूद हैं लेकिन माफकर्ताओ में इसके प्रति उत्साह नजर नही आता हैं. स्मरण रहे, जितना माफी मांगना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण माफ करना है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के युग में बात माफी मांगने तक सीमित लगती नही है, 'कन्ही पे निगाहे -कन्ही पे निशाना' जैसी लगती है. जब माफी मांगो के स्वर में 'कान पकड के माफी मांगो' / 'नाक रगड के माफी मांगो' के स्वर सप्तम में पन्हुच जाते हैं. अरे भाई, कान पकड के (इसकी प्रेक्टिस तो बचपन से होती है) तो ठीक है लेकिन नाक रगड के माफी मांगने में नाक छील जाएगी. बेचारी, नाक का तो ख्याल रखो, नाक है तो सब कुछ है या यू कहे नाक के लिए ही सब कुछ है।

सेहत

बाल मुकुन्द ओझा

लेखक स्तंभकार हैं।

देश की आधी आबादी मोटापे व डायबिटीज की शिकार

आज के जमाने में मोटापा दुनियाभर में बड़ी समस्या बन गया है। शरीर में जब एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, तब यह मोटापे का रूप ले लेता है। यही मोटापा लोगों को कम उम्र में ही बीमारियों का मरीज बना देता है। देश में मोटापा की बढ़ती समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता जायज है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में बहुत से लोग मोटापा से त्रस्त हैं। मोदी ने कहा कि आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की वजह से डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस समस्या के बीच मुझे इस बात का भी संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मुवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटापा दूर करने के लिए अपने खाने में अनहेल्दी फैट और तेल को थोड़ा कम करें।

मोदी की इस पहल का देशवासियों विशेषकर कई अभिनेताओं, डॉक्टरों, स्वास्थ्य संगठनों, खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों ने समर्थन किया है। स्वास्थ्य संगठनों और चिकित्सकों का मानना है पिछले कुछ वर्षों से आयातित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन ने देश के नौनिहालों से लेकर किशोर, युवा और बुजुर्ग तक को अपने आगोश में ले लिया है। इसके फलस्वरूप देश और दुनियाभर में मोटापे की समस्या गंभीर रूप से उत्पन्न हो गई है। विशेषकर वयस्क आबादी इसकी चपेट में आ गई है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को हानिकारक इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें स्वाद और स्वाद को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कृत्रिम योजक या रसायन होते हैं। आप प्रत्येक पैकेज के पीछे लगे लेबल को पढ़कर किसी विशेष खाद्य उत्पाद को बनाने में प्रयुक्त सामग्री की पहचान कर सकते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जिसमें कुल रोगों का 56.4 प्रतिशत हिस्सा असंतुलित आहार के कारण है। अनहेल्दी खाने

की आदतें, जिनमें नमक, चीनी और वसा से भरपूर प्रोसेस्ड फूड का सेवन शामिल है, फास्ट-फूड चेन और पैकेज्ड स्नैक्स की आसान उपलब्धता के कारण यह आदतें तेजी से बढ़ रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है 1990 के बाद से दुनियाभर के वयस्कों में मोटापा दो गुना से अधिक बढ़ गया है। इस अवधि में किशोर आबादी में मोटापा चार गुना बढ़ा है। आयातित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अधिक उपयोग से 2022 तक करीब 43 प्रतिशत व्यस्कों का अधिक वज़न बढ़ा है वहीं 16 प्रतिशत मोटापे के शिकार हुए है। विश्व मोटापा एटलस 2024 के अनुमानों के मुताबिक 2035 तक लगभग 330 करोड़ व्यस्क मोटापे से ग्रस्त होंगे। साथ ही 5 से 19 साल की आयु सीमा के 77 करोड़ से अधिक किशोर और युवाओं को मोटापा घेर लेगा। भारत की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2022 तक सवा सात प्रतिशत से अधिक व्यस्क मोटापे की चपेट में थे। नेशनल फैमिली हेल्थ और मेडिकल पत्रिका लेसेन्ट आदि के अनेक प्रमाणिक सर्वेक्षणों में भी कहा गया है कि हमारे देश में पेट के मोटापे की समस्या सर्वाधिक है। यह समस्या महिलाओं में 40 और पुरुषों में 12 प्रतिशत पाई गई है। स्वास्थ्य के प्रति इस गंभीर खतरें को हमने समय रहते सख्ती से नहीं रोका तो यह देश में नशे से भी अधिक भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगा और इसके जिम्मेदार केवल केवल हम ही होंगे।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में देश में दबे पांव प्रवेश करने वाले जंक फूड जिसे फास्ट फूड भी कहते है ने हमारे सम्पूर्ण पाचनतंत्र पर कब्जा कर स्वास्थ्य के जीवन तंत्र को बिगाड़ कर रख दिया है।

जंक अथवा फास्ट फूड आज घर घर में अल्पाहार के रूप में प्रयोग में लिए जा रहे है। जंक फूड चिप्स, कैंडी, शीतल पेय, नूडल्स, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, क्रिस्प्स, चॉकलेट, मिठाइयाँ, हॉट डॉग जैसे पदार्थों को कहा जाता है। बर्गर, पिज्जा जैसे तले-भुने फास्ट फूड भी जंक फूड की श्रेणी में आती है। जाइरो, तको, फिश और चिप्स जैसे शास्त्रीय भोजनों को भी जंक फूड मानते हैं। जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट, वसा और शर्करा होती है। इसमें अधिकतर तलकर बनाए जाने वाले व्यंजनों में पिज्जा, बर्गर, फ्रैंकी, चिप्स, चॉकलेट, पेटीज मुख्य रूप से शामिल हैं।

सीएम ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत रत्न, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उनकी अद्वितीय संगीत साधना ने भारतीय फिल्म जगत को समृद्ध किया। साथ ही विश्व में असंख्य प्रशंसकों को गीत-संगीत से आनंदित किया। स्वर साम्राज्ञी लता दी अपनी मधुर आवाज के माध्यम से सदैव अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराती रहेंगी।

कवि प्रदीप के देशभक्ति गीत नव ऊर्जा का संचार करने वाले

● जयंती पर किया स्मरण

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के रत्न, कवि एवं गीतकार प्रदीप की जयंती पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कवि प्रदीप के देशभक्ति गीत नव ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। उनकी कृतियों का हर शब्द राष्ट्र सेवा की प्रेरणा और समर्पण को जीवंत कर आज भी सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है।

सीएम ने शूटिंग में रजत पदक प्राप्त करने पर ऐश्वर्य प्रताप को दी बधाई

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (पुरुष) इवेंट में मध्यप्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा रजत पदक प्राप्त करने पर बधाई दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शानदार प्रदर्शन से अर्जित उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान देवास का अकादमिक लीडर्स समिट 8 को

देवास/मोहन वर्मा। प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान, देवास विगत 25 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 8 फरवरी को संस्थान परिसर में अकादमिक लीडर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देवास जिले के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य और निदेशक आमंत्रित किए गए हैं। प्रेस्टीज संस्थान इस पहल के माध्यम से न केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि छात्रों के व्यक्तिगत विकास और उन्हें शिक्षा का सही उद्देश्य समझाने के लिए भी निरंतर कार्य कर रहा है।समिट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख शिक्षाविदों को एक साझा मंच पर लाकर नई शिक्षा नीति (एनईपी) पर विचार विमर्श करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और छात्रों को उनके करियर के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस समिट में नई शिक्षा नीति (एनईपी) पर एक गहन चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें इस नीति के माध्यम से शिक्षा के परिदृश्य में बदलाव की संभावनाओं पर विमर्श किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी हरि सिंह भारती समिट में शामिल होंगे और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन को सम्मानित करेंगे। इस समिट में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय के चांसलर तथा प्रेस्टीज ग्रुप के अध्यक्ष डॉ.डेविश जैन एवं उपाध्यक्ष डिपिन जैन, देवास जिले के सभी प्रमुख शैक्षिक अधिकारी और प्रेस्टीज ग्रुप के सभी कॉलेज के निदेशक भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर पद्मश्री डॉ नेमनाथ जैन ,नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण भी करेंगे। प्रेस्टीज संस्थान द्वारा इस समिट में शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सभी प्राचार्यों और निदेशकों को सम्मानित (फेलिसिटेट) किया जाएगा। समिट में नई शिक्षा नीति के बारे में विमर्श के आधार पर इसे लागू कर, आने वाले भविष्य में छात्र-छात्राओं के भविष्य निर्माण हेतु नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह समिट शिक्षा नीति पर एक साझा दृष्टिकोण बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

नवीन फ्लोरिन ने दो स्कूलों को दी सेनेटरी पैड मशीन की सौगात

देवास । अपने सामाजिक सरोकार के तहत शहर केउद्योग नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल ने दो स्कूलों की बेटियों को सेनेटरी पैड मशीन भेंट की जिसका लाभ तीन सौ से अधिक बालिकाएं ले सकेंगी । नवीन फ्लोरिन के अतुल मौर्य तथा प्रोजेक्ट सहयोगीएक्ट ईव फाउंडेशन अध्यक्ष मोहन वर्मा ने बताया कि येमशीने क्षिप्रा के उच्चतर माध्यमिक शाला तथा पुलिस लाइन स्थित माध्यमिक शाला क्रमांक 7 मे भेंट की गई । कार्यक्रम में अतिथि रूप में महिला बाल विकास अधिकारी रेलम बघेल,पिछड़ा वर्ग सहायक संचालक सपना खरते,जिला जेल फार्मासिस्ट वैशाली भारद्वाज तथा नवीन फ्लोरिन की सीनियर मैनेजर अनिका नाकरा वार्ड पार्षद निधि - प्रवीण वर्मा उपस्थित थी ।

क्षिप्रा स्कूल में प्राचार्य राजीव सूर्यवंशी ने तथा पुलिस लाईन स्कूल में प्राचार्य अशोक साहू ने अतिथियों का स्वागत किया द्य इस अवसर पर अतिथियों ने बालिकाओं को सेनेटरी पैड का महत्व बताते हुए इसे हेल्थ और,हायजीन की दृष्टि से जरूरी बताया और कहा कि बालिकाओं को इस विषय में अनावश्यक चिंता छोड़कर माता पिता और शिक्षिकाओं से खुलकर बात करनी चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए द्य अतिथियों और शाला प्रबंधन ने नवीन फ्लोरिन और एक्ट ईव फाउंडेशन का इस सौगात के लिए आभार माना । कार्यक्रम का संचालन कृष्णकांत शर्मा, किशोर असनानी ने किया वहीं क्षिप्रा में आदिल पठान, कुलदीप बैरागी,रजनीश मलतारे,अर्जुनसिंह बैस,प्रदीप भाटी, ममता सोलंकी,विनीता जैन,पुलिस लाईन स्कूल में जनशिक्षक आतिश कनासे, बालकृष्ण श्रीवास्तव,शीला जोशी,गरिमा बवेले,निर्मलात्रिपाठी, पुष्पा चौहान,जया शर्मा,ज़ाकिर कुरेशी,शकुंतला मालवीय, योगेन्द्र सिंह चावडा उपस्थित थे ।

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 वीं व 11 वीं की प्रवेश चयन परीक्षा आठ को

कक्षा 9 वीं के 679 एवं कक्षा 11 वीं के 93 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल

नरसिंहपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 वीं व 11 वीं की चयन प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को आयोजित की जायेगी। इस वर्ष कक्षा 9 वीं के 679 एवं कक्षा 11 वीं के 93 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन प्रवेश परीक्षा में कक्षा 9 वीं की परीक्षा सुबह 11ः15 बजे से दोपहर 1ः45 बजे तक एवं कक्षा 11 वीं की परीक्षा सुबह 11 बजे से 1ः30 बजे तक जिले के शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडरवारा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीटीआई गाडरवारा में आयोजित की जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी निर्धारित समय से 30 मिनिट पहले प्रवेश पत्र के साथ केन्द्र पर पहुंचे। यह जानकारी प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर ने दी है।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड-2025 में शामिल एनएसएस विद्यार्थियों का किया सम्मान

समाज सेवा ही राष्ट्र की सेवा है - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

समाज के विकास में हर संभव सहयोग देने और सहभागिता बढ़ाने की दी सीख

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र प्रेम की सीख देने की जीवंत इकाई है। इसके नाम से ही सेवा का भाव उत्पन्न होता है। यह संगठन विद्यार्थियों के गुणों का संवर्धन कर उन्हें समुदाय विकास की मूल भावना से ओत-प्रोत कर देश के विकास में सहयोग देता है। यह बेहद प्रशंसनीय है कि आज हमारे विद्यार्थी एनएसएस को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। युवा ही देश का भविष्य हैं और इनमें सेवा भावना के विकास से देश का विकास और अधिक तीव्र गति से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में गणतंत्र दिवस परेड-2025 नई दिल्ली में मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के विद्यार्थियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एनएसएस के समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए परेड में शामिल हुए विद्यार्थियों और उनके समन्वयकों को मैडल देकर सम्मानित किया और शुभाशीष भी दिया। इन एनएसएस विद्यार्थियों ने कर्तव्यपथ, नई दिल्ली में 26 जनवरी 2025 को हुई गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मध्यप्रदेश का नाम रौशन किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं में समाजसेवा, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और साहचर्य की भावना विकसित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों ने इस परेड में बेहतरीन प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों को आगे भी समाजसेवा में हरसंभव सहयोग देने और राष्ट्रीय जागरूकता से जुड़े कार्यों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। युवा ऊर्जा को सही दिशा देकर हम सभी युवाओं की प्रतिभाओं को तराशकर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा देश और प्रदेश के विकास की धुरी हैं। सभी को अपना कॅरियर बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। देश के विकास के लिए युवाओं को राजनीति में भी आना चाहिए। राजनैतिक विकास से ही देश के सामाजिक विकास को बल मिलेगा। युवा सिर्फ रोजगार के पीछे न रहें। वे रोजगार मांगने वाले नहीं, वरन् रोजगार देने वाले बनें। हमारा राष्ट्र वसुधैव कुटुम्बकम की वैश्विक भावना से दुनिया में अच्छाईयां बांटने के लिए जाना जाता है। अच्छाईयां बांटना हमारी संस्कृति है, हमारी जीवनशैली है। इसलिए युवा अपने जीवन के बाकी गुणों के विकास के साथ-साथ सेवा भावना को भी अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एनएसएस द्वारा स्वच्छता, शुचिता, रक्तदान, जनजागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन हमें सह अस्तित्व भाव से जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का एनएसएस बैच लगाकर स्वागत किया तथा प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री ओमप्रकाश सखलेचा, उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक और भोपाल के विभिन्न महाविद्यालयों के एनएसएस स्वयंसेवक भी उपस्थित थे। आभार आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत वरवड़े ने माना।

एनएसएस से जुड़े हैं 1.60 लाख से अधिक विद्यार्थी

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन ने कहा कि एनएसएस शिक्षा द्वारा समाज सेवा और समाज सेवा द्वारा शिक्षा की मूल भावना से कार्य करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के करीब एक लाख 60 हजार से अधिक विद्यार्थी इस संगठन से जुड़े हैं। जिन महाविद्यालयों में एनएसएस नहीं है, वहां भी एनएसएस यूनिट तैयार करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड-2025 में शामिल हुए मध्यप्रदेश के एनएसएस दल के सभी स्वयंसेवकों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र सेवा से जुड़कर सभी विद्यार्थी एक जिम्मेदार नागरिक बनें।

मध्यप्रदेश एनएसएस दल ने दिखाया अनुशासन और सेवा भावना

मध्यप्रदेश से चयनित एनएसएस विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में अनुशासन और समर्पण का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। मध्यप्रदेश का दल पूरे देश से चुने गए एनएसएस के विद्यार्थियों के बीच अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा। कार्यक्रम में सम्मानित विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से चर्चा करते हुए अपने अनुभव साझा किए और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने पर हर्ष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एनएसएस के विद्यार्थियों के साथ समूह चित्र खिंचवाकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी।

पूर्व विधायक प्रतिनिधि के घर पर पुलिस की दबिश

नर्मदापुरम। धारा 354 के आरोपी रहे विधायक प्रतिनिधि प्रकाश शिवहरे के घर पर देहात पुलिस ने दविश देकर खलबली मचा दी, पुलिस यहां प्रकाश शिवहरे के पुत्र विक्की शिवहरे को गिरफ्तार करने पहुंची थी जो नगर में आईपीएल सट्टा खिलाने का कारोबार करता है। करने से पूर्व उसने लिखे तीन पेजी सुसाइड नोट में आत्महत्या करने का कारण आईपीएल सट्टेबाजी और पैसों की दविश देने वालों के नामों का जिक्र किया है उसमें विक्की शिवहरे, आकाश मोबाइल, ऋषि सराठे, भैय्यू सराठे, आईपीएल सट्टेबाजी सरगना कहा है। ऋषि सराठे सट्टेबाजों की गिरफ्त में था क्या वह भी इनके कारण आत्महत्या करने को मजबूर हुआ..? जो भी हो पुलिस अब इसकी जांच गंभीरता से कर रही। अमित दीवान की आत्महत्या ने जिसकी कलई खोल दी, विधायक प्रतिनिधि का पुत्र आईपीएल सट्टा खिलाने वाले में

सर्व विप्र समाज ने आज पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर आईपीएल सट्टेबाजी कर रहे विक्की शिवहरे सहित अन्य सात लोगों के उपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर कारवाई को लेकर तंज कसा है, ज्ञापन में लिखा है कि जब अपराधियों पर शासन द्वारा बुलडोजर चला दिया जाता तो इन पर मेहरबानी क्यों .. गौरतलब होगा आईपीएल सट्टेबाजी को लेकर दो दिन पहले अमित दीवान ने एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या तो जिला बदर सजायाफ्ता है। फिर सुसाइड नोट में छह माह पहले आत्महत्या कर चुके अमित उपाध्याय के नाम का भी जिक्र किया आया है। अमित उपाध्याय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के करीबी महेश उपाध्याय के बड़े भाई का पुत्र है जसकी आत्महत्या करने का अब तक रहस्य बना हुआ था। वह भी खुलता नजर आ रहा है। अमित उपाध्याय क्या अन्य युवाओं की भांति कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आईपीएल शामिल होना एक तरीके से विधायक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। जिन्होंने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को न केवल ढांढस बंधाया साथ ही पुलिस अधिकारी से मिलकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि विधायक प्रतिनिधि रहे प्रकाश शिवहरे के उपर महिला के साथ छेड़खानी करने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने जैसें गंभीर एफआईआर दर्ज है।

दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया त्यौहार

नरसिंहपुर। वीरांगना क्लब की पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बसंत पंचमी एवं नर्मदा जयंती को लेकर दिव्यांग बच्चों के बीच छात्रावास में जाकर यह त्यौहार मनाया। मां सरस्वती की पूजन कर सरस्वती वंदना की क्लब की पूर्व अध्यक्ष पूनम जैन ने अपने जीवन साथी सुलभ जैन एडवोकेट के जन्म दिवस पर दिव्यांग बच्चों को स्वलपाहार व फल का वितरण किया और बच्चों को टी शर्ट भेंट की। उपस्थित सदस्य पूर्व ए.आ.अर्चना राय,मल्टीपल डा. रुपकला कटारे, पूर्व अध्यक्ष पूनम जैन , वर्तमान अध्यक्ष सविता महोविया ,सचिव पूनम धुर्वे, कोषाध्यक्ष रजनी राजोरिया , ज्योत्सना राय , रेनू नोरिया आदि मौजूद रहीं।

मप्र को लगातार 7 बार मिले हैं कृषि कर्मण अवार्ड

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयास से कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। मध्यप्रदेश को वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। मध्यप्रदेश वर्ष- 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 में कुल खाद्यान्न केटेगरी के लिए, वर्ष- 2013-14, 2015-16 एवं 2016-17 में गेहूं फसल के लिये और वर्ष 2017-18 में दलहन फसल के लिये कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। वर्ष- 2022 में मध्यप्रदेश के भू-अभिलेखों के एकीकरण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश में गेहूं, उड़द, मसूर, सोयाबीन, अलसी, फसलों का क्षेत्राच्छादन सबसे अधिक है।

सड़कों की क्वालिटी में गुणत्ता लाने इंस्पेक्शन

साफ्टवेयर से चिन्हित की सड़कें, सात जिलों में मंत्री के निर्देश पर हुई औचक जांच

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के काम में कसावट लाने के लिए सड़कों के निर्माण का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। सभी सात जिलों में पांच-पांच निर्माण कार्यों को औचक निरीक्षण करने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थान चिह्नित किए गए। इंस्पेक्शन किए गए तीन कार्य निर्माणाधीन थे एवं दो कार्य परफॉर्मेंस गारंटी वाले थे। इन 5 निर्माण कार्यों में से एक कार्य भवन निर्माण का था। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर विभाग के सातों परिक्षेत्रों के एक-एक जिले में मुख्य अभियंताओं के दलों ने औचक निरीक्षण किया।

रेंडम आधार पर किया गया जिलों का चयन - औचक निरीक्षण के लिये सात जिलों का चयन रेंडम आधार पर किया गया, जिसमें भोपाल परिक्षेत्र से भोपाल, ग्वालियर परिक्षेत्र से ग्वालियर, जबलपुर परिक्षेत्र से कटनी, इंदौर परिक्षेत्र से धार, रीवा परिक्षेत्र से शहडोल, उज्जैन परिक्षेत्र से रतलाम एवं सागर परिक्षेत्र से पन्ना जिला शामिल था।

राष्ट्रीय डॉग स्क्वायड प्रतियोगिता में 8-डॉग्स करेंगे एमपी का प्रतिनिधित्व

सूंघने, हाई जंप और खोई चीजें ढूंढने में माहिर; भोपाल में चल रही खास ट्रेनिंग

भोपाल (नप्र)। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस मीट में होने वाली डॉग प्रतियोगिता में भोपाल से 8 डॉग प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन सभी की मध्यप्रदेश पुलिस डॉग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है। असिस्टेंट कमांडेंट नीरज ठाकुर ने बताया कि ये डॉग्स राष्ट्रीय डॉग स्क्वायड प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जो रांची (झारखंड) में आयोजित होगी। वहीं, पुलिस मीट के दौरान अलग-अलग राज्यों की टीमें कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। यह मीट 10 से 15 फरवरी तक चलेगी। इस समय सभी डॉग्स की तैयारी जोरों पर है। पिछली बार यह पुलिस मीट लखनऊ में हुई थी, जिसमें मध्यप्रदेश पुलिस ने 40 मेडल जीते थे। प्रतियोगिता के लिए डॉग्स की विशेष ट्रेनिंग प्रधान आरक्षक ग्यास उद्दीन खान करवा रहे हैं। इस टीम में संदीप परिहार, रामचंद्र भारती, शैलेंद्र, दीपक, बालकराम, नीरज डहरीया और रामचंद्र शामिल हैं।

स्क्वायड में 52 नए डॉग्स शामिल होंगे - असिस्टेंट कमांडेंट ने बताया कि ऑल इंडिया लेवल पर हैदराबाद से 52 नए डॉग्स की खरीद की जा रही है। इसमें डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर जैसी कई ब्रीड के डॉग्स शामिल हैं। ये डॉग्स फरवरी महीने के अंत तक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाएंगे। निरीक्षक प्रकाश नारायण शर्मा के मुताबिक इन डॉग्स की खरीद उनकी सूंघने की क्षमता, स्वभाव, कद और शारीरिक बनावट जैसे कई शारीरिक मापदंडों की जांच के बाद की जाती है। खरीद के बाद डॉग्स और उनके ट्रेनर्स की संयुक्त ट्रेनिंग होती है। ट्रेनर्स की बेहतर ट्रेनिंग के लिए कई सेशन और अध्ययन कराया जाता है।

ट्रेनिंग के बाद प्रदेशभर के जिलों में तैनाती - निरीक्षक प्रकाश नारायण शर्मा ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद डॉग्स की तैनाती अलग-अलग जिलों में होती है। इसके बाद ये डॉग्स केस सॉल्व करने, गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस, स्मृति दिवस और पुलिस समिट में भाग लेते हैं।

लगभग 8 घंटे का ट्रेनिंग रूटीन - डॉग निरीक्षक केसर सिंह ने बताया कि आमतौर पर सुबह 6 से 11 बजे और फिर दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक डॉग्स की ट्रेनिंग होती है। लेकिन प्रतियोगिता के चलते फिलहाल रात में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन डॉग्स की डाइट पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार तय होती है। अमूमन यह दिन में दो बार डाइट लेते हैं, जिसमें दूध, रोटी, पैडिग्री और नॉनवेज शामिल हैं। इनकी ट्रेनिंग में कुछ खास ट्रिक्स और सहायक इक्यूपमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है।

रूमालों की सुगंध पहचानने की भी दी जा रही ट्रेनिंग - प्रतियोगिता में भाग लेने वाले डॉग्स को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें रूमालों की सुगंध पहचानने की ट्रेनिंग भी शामिल है। इस ट्रेनिंग में डॉग्स एक व्यक्ति के हाथ से मलाए गए रूमाल को कई अन्य रूमालों के बीच से पहचान लेते हैं। इसके अलावा खोए सामान को वापस लाने, हाई जंप और परेड प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है।

कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर पहुँचकर किया विद्यार्थियों से संवाद

सकारात्मकता, आत्मविश्वास और मेहनत सफलता की कुंजी- कलेक्टर

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने चीचली विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए अपने जीवन के अनुभव साझा किये। कलेक्टर श्रीमती पटले ने विद्यार्थियों से कहा कि सकारात्मकता, आत्मविश्वास और मेहनत सफलता की कुंजी हैं। उन्होंने असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेने और आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा आपका मुकाबला सिर्फ आपसे है, अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर किसी की परिस्थितियां

अलग होती हैं, और दूसरों की राय से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे दूर कर ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। यहाँ प्राचार्य श्री गजेन्द्र सिंह कौरव और स्टाफ द्वारा बेहद आकर्षक तरीके से विभिन्न विद्यालयीन गतिविधियाँ, शिक्षण कार्य, खेलकूद, बेहतर वार्षिक परिणाम और अन्य कार्य का क्रियान्वयन किया गया है। ज़िले के शासकीय विद्यालयों के लिए यह विद्यालय एक उदाहरण पेश करता है। यहाँ विद्यार्थी की ड्रेस साफ़ सुथरी, ब्लेजर, टाई के साथ आते हैं। आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व की पहचान होता है। अपनी पर्सनालिटी को विकसित करें। संवाद कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कहा कि वे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी प्राथमिकता आपकी पढ़ाई और आपका भविष्य है। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें और इसका उपयोग सिर्फ अपनी पढ़ाई या जरूरी जानकारी के लिए करें। उन्होंने कहा कि जीवन में हर किसी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लें और उसे अपनी प्रेरणा बनाएं। एक छात्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। उन्होंने कहा, जीवन में हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। उसे अपनाएं और आगे बढ़ें। इस दौरान ज़िला पंचायत सीईओ श्री दलीप कुमार, ज़िला शिक्षा अधिकारी, एनटीपीसी से श्री संदीप साखरे सहित अन्य अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे।

एम्स में औषधि और उपकरण निगरानी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान कें फार्माकोलॉजी विभाग और सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस, इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'SoPICON 2025' का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ एक ज्ञानवर्धक पूर्व-सम्मेलन कार्यशाला के साथ हुआ, जिसमें देशभर से शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और छात्रों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य औषधि निगरानी और उपकरण निगरानी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना है। इस कार्यशाला की शुरुआत आयोजन अध्यक्ष डॉ. बालकृष्णन एस (प्रोफेसर एवं फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष, एम्स भोपाल) द्वारा स्वागत भाषण और परिचय के साथ हुई। इसके बाद डॉ. रतींदर झाज (फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर एवं आरटीसी-फार्माकोविजिलेंस के समन्वयक, एम्स भोपाल) द्वारा औषधि निगरानी का अवलोकन तथा डॉ. शिल्पा एन. कौरे (प्रोफेसर एवं आरटीसी- मैटेरियोविजिलेंस

समन्वयक, एम्स भोपाल) द्वारा उपकरण निगरानी का अवलोकन प्रस्तुत किया गया।

फार्माकोविजिलेंस कार्यशाला में प्रतिभागियों को डॉ. एस.पी. धनेरिया (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आरजी गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन) द्वारा कारण निर्धारण पर व्यावहारिक सत्र का प्रशिक्षण दिया गया। श्रीमती दीपा चौधरी (फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, एम्स भोपाल) ने विगीफ्लो कॉ प्रदर्शन किया, जबकि डॉ. अनामिका दत्ता (मेडिकल ऑफिसर, MedDRA MSSO, बेंगलुरु) ने MedDRA कोडिंग पर सत्र का संचालन किया। श्री गिर्जेश विश्वकर्मा (गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल) ने MAH ICSRs की प्रक्रिया पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त, सुश्री मोलीशा सोनी (फिडेलिटी हेल्थ सर्विसेज) ने PV डेटा सेट/सॉफ्टवेयर (PvEdge) का प्रदर्शन किया।

मैटेरियोविजिलेंस कार्यशाला में डॉ. अहमद नजमी (डिप्टी कोऑर्डिनेटर, आरटीसी- मैटेरियोविजिलेंस, एम्स भोपाल) ने MDAE रिपोर्टिंग टूल्स और कारण निर्धारण पर एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया। श्री मोहम्मद फैजान खान (MvPI रिसर्च एसोसिएट) ने केस आधारित चर्चा की, जबकि डॉ. शत्रुंजय शुक्ला (सहायक वैज्ञानिक, IPC, गाजियाबाद) ने ADRMS सॉफ्टवेयर पर व्यावहारिक सत्र प्रदान किया। इस कार्यशाला में यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. देबाशीष कौशल, डर्मेटोलॉजी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉ. फेबिन अशरफ, और रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोग्राफर श्री अभिषेक शेरावत ने अपने अनुभव साझा करके कार्यशाला को समृद्ध किया। कार्यशाला का समापन फार्माकोविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस क्विज़ के साथ हुआ, जिसे डॉ. फ्लोरेंस जॉय और डॉ. सौम्या सिंह (सीनियर रेजिडेंट, फार्माकोलॉजी विभाग, एम्स भोपाल) द्वारा आयोजित किया गया।

उद्घाटन समारोह में प्रो. (डॉ.) बर्था ए.डी. रथिनम (प्रोफेसर एवं प्रमुख, एनाटॉमी विभाग, एम्स भोपाल) द्वारा संबोधन हुआ। इस सम्मेलन में विश्वभर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। प्रो. (डॉ.) संदीप अग्रवाल (अध्यक्ष SoPI) और प्रो. (डॉ.) सैयद जियाउर रहमान (सचिव SoPI) भी सभा को संबोधित करेंगे। डॉ. शांति पाल (टीम लीड, फार्माकोविजिलेंस मेडिसिन्स और स्वास्थ्य उत्पाद, WHO मुख्यालय) द्वारा मुख्य वक्तव्य दिया जाएगा। सम्मेलन में समानांतर संगोष्ठियां, मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियां, फार्माकोविजिलेंस क्विज़, समापन समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शामिल होंगे।कार्यपालक निदेशक प्रो. सिंह ने इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, SoPICON 2025 औषधि निगरानी और उपकरण निगरानी के दृष्टिकोण से रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह सम्मेलन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और शोधकर्ताओं को सहयोग और ज्ञान साझा करने के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में सक्षम बनाएगा। यह सम्मेलन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और आम जनता के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा पर जागरूकता और ज्ञान साझा करने का एक ऐतिहासिक आयोजन साबित होगा।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में पेसमेकर क्लीनिक का उप मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

● नि:शुल्क जांच की मिलेगी सुविधा

भोपाल । उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रारंभ की जा रही पेसमेकर क्लीनिक

हृदय रोगियों के लिए वरदान होगी। जटिल ऑपरेशन के उपरांत लगाए जाने वाले पेसमेकर की जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस क्लीनिक में मरीजों को निःशुल्क जांच की सुविधा मिलेगी। यह स्पेशल क्लीनिक हर माह के प्रथम गुरुवार को संचालित होगा, जिसमें प्रातः 9 बजे से दोपहर एक बजे तक मरीज अपनी जांच करा सकेंगे। भविष्य में इस सुविधा के विस्तार के भी कार्य होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पेसमेकर क्लीनिक का शुभारंभ किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विंध्य क्षेत्र में असाध्य रोगों के उपचार के लिए वरदान बन गया है। यहाँ कुशल चिकित्सकों द्वारा मरीजों का कुशलता पूर्वक उपचार किया जा रहा है और उन्हें जटिल आपरेशन व अन्य उपचार के लिए बाहर जाने से मुक्ति मिल गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा को मेडिकल हब बनाने तथा चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लगातार प्रयास जारी हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एमआरआई मशीन के लिए बनाए जा रहे स्थल का निरीक्षण किया तथा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि एमआरआई मशीन जल्द स्थापित कराई जा सके। डीन मेडिकल कॉलेज डॉ सुनील अग्रवाल, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉ अक्षय श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी विभाग डॉ व्हीडी त्रिपाठी, डॉ एसके त्रिपाठी सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।

एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत

एसएसयूआई ने आचार संहिता उल्लंघन के लगाए आरोप

भोपाल। एनएसयूआई ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉ. सचिन कुचिया के खिलाफ चुनाव संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के परीक्षा नियंत्रक डॉ. सचिन कुचिया के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिंह को की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉ. कुचिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार किया, जो कि स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान जारी था। उसी दिन यह सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी। ऐसे में एक प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है। परमार ने कहा कि इससे न केवल विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची है बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। रवि परमार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर डॉ. सचिन कुचिया के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की आचार संहिता के उल्लंघन को रोका जा सके। शिकायत के साथ संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट और वीडियो भी निर्वाचन आयोग को ईमेल किए हैं एनएसयूआई ने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करे।

पोषण आहार सप्लाई में 110 करोड़ का घोटाला

●परिवहन अमला भी संलिप्त : मुकेश नायक ●स्कूटर, मोटरसाईकिल के नंबर आये सामने, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ भ्रष्टाचार उजागर

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पोषण आहार योजना में हुये भ्रष्टाचार को उजागर करते हुये बताया कि मध्यान्ह भोजन के तहत 88119 केंद्र हैं, जिनमें 1 करोड़ 9 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्यान भोजन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए इन बच्चों को 2190 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं प्रदेश में 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 84465 आंगनबाड़ी केंद्र और 12670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसमें 80 लाख हितग्राही बच्चों को पोषण आहार देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, योजना में 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। यानि 12 रू. प्रति बच्चें मप्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 18 रू. का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, लेकिन इस निर्णय कर कोई दिखाई देने वाली कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई।

श्री नायक ने कहा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, कई बच्चो की मौत हो गई, उनके नाम का राशन भी सरकार द्वारा निकाला जा रहा है। क्या 100 फीसदी बच्चों रोज स्कूल आते हैं? मध्यान्ह भोजन शुरूआते में आकर्षण का केंद्र था, लेकिन धीरे-धीरे यह योजना बच्चों के लिए कोई बड़ा आकर्षण नहीं रहीं, ऐसी स्थिति में 40 प्रतिशत बच्चों स्कूलों में नहीं आते, इतनी लचर, अव्यवस्थित और गुणवत्ता विहीनता के बाद भी 201 करोड़ का पुरूस्कार भी सरकार ने ले लिया, और गलत तरीके से पुरूस्कार का उल्लेख भी सीएजी की रिपोर्ट में किया गया है।

श्री नायक ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमडीएम योजना 1995 से लागू की गई, योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 100 ग्राम मिडिल स्कूल के बच्चों को 150 ग्राम गेहूं अथवा चावल दिया जाता है। वहीं प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान की आपूर्ति की जाती है।

श्री नायक ने कहा कि मनुष्य में दया, करूणा, मानवता, उदारता होती है, लेकिन सरकार में बैठे लोग अपने ही बच्चों का अनाज खा रहे हैं, और अपने ही बच्चों को खा जाने का स्वभाव जानवरों में होता है, जिस राज्य का 50 प्रतिशत अनाज सरकार खा जाये तो यह पशुओं से ज्यादा भयावह लोग सरकार में बैठे है।

श्री नायक ने बताया कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पोषण आहार में हुये भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें परिवहन विभाग भी संलिप्त है। पोषण आहार सप्लाई में परिवहन करने वाले वाहनों में स्कूटर, मोटर साईकिल का उपयोग किया गया है, जिससे एक साथ सैकड़ों क्विंटल माल सप्लाई का हवाला दिया गया है। सरकार का पोषण आहार सप्लाई में 110 करोड़ का घोटाला कर भ्रष्टाचार का बड़ा कारनामा है। एक और सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार मप्र में 428 करोड़ के मध्यान भोजन योजना में घोटाला सामने आया है। श्री नायक ने कहा कि कुपोषण के मामले में भारत दुनिया में नंबर एक पर हैं, वहीं देश में मप्र कुपोषण के मामले में नंबर एक पर है। गलत आंकड़े देकर पोषण आहार के नाम पर पुरूस्कार लिया गया है। वहीं 2000 करोड़ का फंड पोषण आहार के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई। इन बीस सालों में जिन बच्चों की मृत्यु हो गई वे योजना में रजिस्टर्ड हैं, योजना को संचालित करने वाले जो व्यवस्थापक हैं वे ही बच्चों के पोषण आहार की राशि डकार गये।

योजना में हुये भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण कड़ी परिवहन विभाग भी है, जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, परिवहन के लिए उपयोग किये गये जो नंबर दिये गये हैं, उसमें मोटर साईकिल, स्कूटर हैं, जिसमें पांच-पांच क्विंटल अनाज का परिवहन किया गया हैं, इसका पता लगाया गया तो बताया गया कि वह कंडम हो गई और वर्कशॉप में पड़ी हुई हैं।

आयुष विभाग द्वारा गौहरगंज के गर्ल्स हाई स्कूल में हेल्थ कैंप का आयोजन

भोपाल । एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में आयुष विभाग द्वारा गौहरगंज के गर्ल्स प्राइमरी हाई स्कूल में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। प्रो. सिंह वंचित आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के प्रबल समर्थक हैं। इस दौरान गौहरगंज में गर्ल्स प्राइमरी हाई स्कूल के बच्चों को योग का विशेष सत्र भी कराया गया, जिसमे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी हिस्सा लियाद्य इस कैंप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को तनाव प्रबंधन, अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। इसमें कुल 47 बच्चे और शिक्षक शामिल थे।

आयुष विभाग की तरफ से मेडिकल ऑफिसर डॉ तारिक बरकती और योग प्रशिक्षक चंचल सूर्यवंशी उपस्थित रहे। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि आजकल छात्रों को पढ़ाई के दौरान मानसिक दबाव और तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी एकाग्रता और सीखने कीॉ क्षमता प्रभावित होती है। योग और ध्यान (मेडिटेशन) को अपनाकर छात्र अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और ध्यान जैसी तकनीकों को अपनाने से मानसिक शांति मिलती है और अध्ययन में रुचि बढ़ती है।

विशेषज्ञों ने बच्चों को इन योग क्रियाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन भी करके दिखाया। इसके अलावा विशेषज्ञों ने बच्चों को संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों के लाभ बताए, ताकि वे जंक फूड, अत्यधिक मीठे और तले-भुने खाद्य पदार्थों से दूर रह सकें। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बच्चों को अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि हर छात्र को अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए और नियमित दिनचर्या अपनाकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। छात्रों को अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई, जिससे उनका ध्यान अध्ययन पर केंद्रित रह सके।

प्रो. सिंह ने इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में आयुष विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने और तनाव प्रबंधन के लिए योग एक प्रभावी साधन है। इस तरह के स्वास्थ्य शिविर न केवल छात्रों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति भी प्रेरित करते हैं। एम्स भोपाल अपने मिशन के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ईमानदारी की मिसाल,खोया मोबाइल यात्री को लौटाया

भोपाल। भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की यात्री सेवा और ईमानदारी का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया। ग्वालियर से भोपाल आ रहे यात्री नितेश मंगरिया का कीमती एंड्रॉयड मोबाइल फोन ट्रेन संख्या 12648 कोंगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस से उतरते समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गिर गया, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। फोन को वाणिज्य बुकिंग क्लर्क श्रीमती अंकिता पटेल ने देखा और ईमानदारी दिखाते हुए इसे उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) श्री अशोक नागर के सुपुर्द कर दिया। कुछ समय बाद जब यात्री के परिजनों का फोन उसी मोबाइल पर आया, तो श्री अशोक नागर ने उन्हें मोबाइल सुरक्षित होने की जानकारी दी। बाद में जब श्री नितेश मंगरिया भोपाल स्टेशन पर पहुंचे, तो उन्होंने रेलवे प्रशासन और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें और किसी भी असुविधा की स्थिति में रेलवे हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर ग्रामीण विकास के करें कार्य : उप मुख्यमंत्री

भोपाल। उप मुख्यमंत्री ने श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस रीवा में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय जन प्रतिनिधि व शासकीय अधिकारी समन्वय बनाकर ग्रामीण विकास के कार्य करें। उन्होंने रीवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पंचायत के सरपंचों से कहा कि अपनी ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास की नवीन सूची में शामिल करने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत में सबसे ज्यादा नाम शामिल होंगे उसे विधायक निधि से 10 लाख रूपये दिये जायेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा के भुगतान तथा आरईएस द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा की। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, ग्राम पंचायतों के सरपंच सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल में अकाउंटेंट को लूटने वाले 3 गिरफ्तार

भोपाल। भोपाल में बंसल वन के अकाउंटेंट से 2 लाख रुपए की लूट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की प्लानिंग बंसल वन में ही काम करने वाले एक पूर्व ड्राइवर ने रची थी। मामले में एक आरोपी फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी अवधेश तोमर और उनकी टीम ने 35 बदमाशों से पूछताछ भी की।

बावड़िया चौराहे से आशिमा मॉल तक बनने वाले आरओबी का निर्माण जल्द शुरू होगा

राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने निर्माण कार्यों से जुड़ें विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

भोपाल। बावड़िया चौराहे से आशिमा मॉल तक नया आरओबी (रेलवे ओव्हर ब्रिज) का निर्माण जल्द शुरू होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने बुधवार को निवास कार्यालय पर आरओबी निर्माण से जुड़े विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आरओबी निर्माण के लिये भू-अर्जन की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाये।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने इस आरओबी निर्माण से नर्मदापुरम रोड पर यातायात बेहतर होगा। इस क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों

को सुगमता होगी। उन्होंने कहा कि भोपाल विकास प्राधिकरण, नगर निगम, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग और लोक निर्माण विभाग सहित निर्माण कार्यों से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर आरओबी निर्माण की जिम्मेदारी से अवगत कराये जाये।

बैठक में एडीएम श्री सिद्धात जैन, एसडीएम श्री रवि शंकर राय और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। आरओबी के संबंध दी गई जानकारी में बताया गया कि 733 मीटर लंबे आरओबी और 310 मीटर के एप्रोच रोड का निर्माण होगा। आरओबी के निर्माण हो जाने से नर्मदापुरम रोड पर ट्रैफिक का दबाब कम होगा और यातायात सुगम होगा।

गुना में श्रद्धालुओं की ट्रॉली पलटी

दो मौत, 37 घायल, महाकुंभ से लौट रही कार मंदसौर में 8 बार पलटी खाई, दंपती की गई जान

गुना (नप्र)। गुना के कंचनपुरा से राजस्थान जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रॉली फतेहगढ़ में पलट गई। हादसे में एक बुजुर्ग और बच्ची की मौत हो गई। 37 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार सुबह 11.30 बजे हुआ।

ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार थे। सभी राजस्थान के बारां में गूगोर वाली माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी किशनपुरा के पास मोड़ पर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इधर, मंदसौर के गरोठ-जावरा मार्ग पर प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे परिवार की कार का टायर फट गया, जिससे कार 8 बार पलटी खाई। हादसे में दंपती की मौके पर ही मौत हो गई। बेटा-बेटी समेत 5 लोग घायल हैं। वहीं, छतरपुर के बिजावर में अचानक सड़क पर आए बंदर को बचाने के चक्कर में बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए।

मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

गुना हादसे में ट्रॉली में सवार चिरोंजी लाल लोधा (60) और रमा बाई (10) की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा कर दिया और अस्पताल के रिसेप्शन के कांच फोड़ दिए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। श्रद्धालु राजस्थान के बारां जिले में गूगोर वाली माता मंदिर पर माघ महीने में एक महीने मेला लगता है। इस दौरान गुना, अशोकनगर सहित कई जिलों के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गुना के कंचनपुरा से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे थे।

सभी सेक्टर को एक साथ जोड़ने का माध्यम सहकारिता :सहकारिता मंत्री सारंग

राज्य ऋण संगोष्ठी में हुआ सराहनीय प्रदर्शन करने वाले हितग्राहियों का विशेष सम्मान

भोपाल । सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि किसी भी देश के उन्नयन, विकास और जनता के कल्याण के लिये अर्थ-व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि जहाँ व्यक्ति है, वहाँ अर्थ है और जहाँ अर्थ है वहाँ अर्थ-व्यवस्था। विकसित भारत निर्माण की परिकल्पना के लिये अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये संकल्प के साथ प्लानिंग करनी होगी। सभी अर्थ-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये लक्ष्य के साथ अपने-अपने प्रकल्प पर काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर को एक साथ जोड़ने का माध्यम सहकारिता है। मंत्री श्री सारंग गुरूवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राज्य ऋण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश की हर पंचायत पर स्थापित होगा पैक्स

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि ऋण देना और समय पर वापस लेना अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। उन्होंने कहा कि एक जैसे सेक्टर के लोग लगातार संवाद करें। समन्वय और परिस्थिति को जांचते हर तीन माह में एक-दूसरे की अपेक्षाओं पर काम करने से और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता का महत्वपूर्ण स्तम्भ संस्कार है। पारदर्शिता और कम्प्यूटराइजेशन के साथ अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये सुधार आवश्यक है। सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये मध्यप्रदेश की हर पंचायत पर पैक्स स्थापित किये जायेंगे।

अर्थ-व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिये मध्यप्रदेश दृढ़ संकल्पित

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक में सहकारी आन्दोलन के माध्यम से नये रोजगार के अवसर सृजित कर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिये काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाचार विंग के माध्यम से नित नये आयाम के द्वार खोले जा रहे हैं। प्रदेश में समितियों का फेडरेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कॉर्पोरेट कल्चर को अपना कर बौद्धिक कुशलता और रोजमर्रा की कार्यप्रणाली पर काम किया जा रहा है। अर्थ-व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिये मध्यप्रदेश दृढ़ संकल्पित है। देश को तीसरे नंबर की इकॉनोमी वाला बनाने के लिये मध्यप्रदेश जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है।

मंत्री श्री सारंग ने राज्य फोकस पेपर 2025-26 पुस्तिका और सफल नवाचार की कहानियों पर आधारित नैब-पहलें का विमोचन किया। संगोष्ठी में सहकारी संस्थाओं को नाबार्ड की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति-पत्र वितरण और राज्य में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले हितग्राहियों का विशेष सम्मान किया गया।

संगोष्ठी को आरबीआई की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री रेखा चन्दनवेली, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री चन्द्रशेखर शर्मा और नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सुश्री सी. सरस्वती ने भी विचार व्यक्त किये। इस मौके पर सहकारिता आयुक्त श्री मनोज पुष्प, एस.एल.बी.सी. के डीजीएम श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित थे। संगोष्ठी में राज्य फोकस पेपर 2025-26 पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

॥ मंदिरम् ॥

30

लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, कर्नाटक

लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले के नुग्गेहल्ली गांव में होयसल वास्तुकला वाला 13वीं सदी का हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। त्रिकुटा वैष्णव परिसर केशव, लक्ष्मी नरसिंह और वेणुगोपाल को समर्पित है। इसका निर्माण 1246 ई. में राजा वीर सोमेश्वर के अधीन होयसल साम्राज्य के एक सेनापति बोम्मन्ना दंडनायक ने करवाया था। यह मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है, लेकिन इसमें अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। मुख्य मंदिर के उत्तरी गर्भगृह में भगवान नरसिंह की मूर्ति, पश्चिमी गर्भगृह में केशव की छवियाँ और दक्षिणी गर्भगृह में वेणुगोपाल की छवियाँ हैं। यह मंदिर अपनी वैष्णव नक्काशी, हरिहर, दक्षिणमूर्ति, चंडीकेश्वर और गणेश की शैव नक्काशी, दुर्गामहिषासुर मर्दिनी, नृत्य करती लक्ष्मी और सरस्वती की शक्ति नक्काशी और सूर्य और ब्रह्मा जैसे वैदिक देवताओं के लिए जाना जाता है।

स्कूटी खरीदने के लिए सभी जिलों को राशि भेजी गई है : मुख्यमंत्री

- प्रावीण्य सूची में शामिल विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि भी जल्द ही मिलेगी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रावीण्य सूची के बच्चों को स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। अब बच्चे अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सकते हैं। इसके लिए सभी जिलों को राशि पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आधुनिक समय में बच्चों के बौद्धिक विकास में लैपटॉप सहायक है, जल्द ही कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि अंतरित की जाएगी। विद्यार्थियों को जो अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के बल पर उपलब्धि अर्जित कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना राज्य शासन का दायित्व है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से जो विद्यार्थी प्रावीण्य सूची में आ रहे हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्कूटी और लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं।

मौसम बदलते ही ऊंट के काफिले ने भोपाल में प्रवेश किया। फोटो- प्रवीण वाजपेयी

प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी

फरवरी में पहली बार ठिठुरन ; पचमढ़ी में 21.6 डिग्री रहा पारा, भोपाल-इंदौर में भी गिरावट

भोपाल (नप्र)। बर्फीली हवा चलने की वजह से फरवरी में पहली बार गुरुवार को मध्यप्रदेश फिर से ठिठुर गया। भोपाल में 18 से 20 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली, जबकि इंदौर एयरपोर्ट पर यह 34 से 36 किमी प्रतिघंटा रही। पूर्वी हिस्से में भी तेज हवा चली। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया, उत्तर भारत में बर्फबारी होने से सर्द हवा चल रही है। जिसका असर मध्यप्रदेश में देखने को मिल रहा है।गुरुवार को प्रदेश के एकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 21.6 डिग्री दर्ज किया गया। रायसेन में 23.2 डिग्री, धार में 23.7 डिग्री, नौगांव-रीवा में 24 डिग्री, सिवनी में 24.2 डिग्री, सीधी में 24.4 डिग्री, उमरिया-सागर में 25.1 डिग्री, सतना में 25.3 डिग्री, दमोह-गुना में 25.5 डिग्री और बैतूल में 25.7 डिग्री रहा।बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 25.8 डिग्री, इंदौर में 23.5 डिग्री, ग्वालियर में 25.4 डिग्री, उज्जैन में 25 डिग्री और जबलपुर में 23.8 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार-गुरुवार की रात में भी पारे में गिरावट देखने को मिली। इस वजह से पारा फिर से 10 डिग्री से नीचे आ गया।

अब पारे में गिरावट का दौर

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान जताया है। ऐसे में कुछ शहरों में रात का तापमान फिर से 10 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है। अभी पारा इससे अधिक ही है।

8 फरवरी से नया सिस्टम, 10 के बाद दिखेगा असर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 8 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव होने की संभावना है। इस वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया, 12, 13 और 14 फरवरी को बारिश होने का अनुमान है। 20 फरवरी के बाद ठंड का असर और कम होगा। जिससे दिन-रात दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वर्तमान में भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है।

विधायक मसूद ने वक्फ सर्वे को लेकर लिखा लेटर

- जेपीसी चेयरमेन, लोकसभा स्पीकर और मुख्य सचिव के नाम पत्र में सर्वे रोकने की मांग की

भोपाल (नप्र)। वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मसूद ने कहा, सर्वे के लिए जो नियम फॉलो किए जा रहे हैं, उसके कारण आने वाले समय में विवाद होगा।

आरिफ मसूद ने तीन आपत्तियां जताई

राजस्व गजट 1983 से 1989 प्रकाशित होने के बाद मध्य प्रदेश में मिसल बंदोबस्त हुआ था। जिस कारण राजस्व एंट्री मिलान में दिक्कत आना स्वाभाविक है। मांगी गई जानकारी में मध्य प्रदेश राज्य पत्र में दर्ज संपत्तियों में मुजावरों के नाम दर्ज हैं, या उक्त भूमिया शासकीय नामों से दर्ज हैं या अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। सच ये है की वक्फ की जमीनों पर खसरों में 'वक्फ बोर्ड अ-अहस्तांतरणीय' लिखा जाना आवश्यक है।

वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे

मसूद ने कहा- वक्फ बोर्ड अ-अहस्तांतरणीय नाम के दुरूस्तीकरण करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट में मामला होने के चलते फिलहाल इस पॉइंट के संबंध में कोई भी जानकारी देना न्यायोचित नहीं होगा।

बुंदेलखंड के दो हजार तालाबों को पुनर्जीवित करेगी सरकार

केन-बेतवा के साथ ही चंदेलकालीन वाटर बॉडीज में रोका बारिश का पानी

भोपाल (नप्र)। 'बुंदेलखंड' के नाम के साथ ही सूखा ग्रस्त इलाका, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पानी के संकट से जूझते इस पूरे इलाके को पानीदार बनाने के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो महीने पहले 25 दिसंबर को खजुराहो में किया था। इस नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही बुंदेलखंड रीजन में दो हजार चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने सरकार काम करेगी। चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने में मप्र का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संरक्षण पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं (एनजीओ), और पब्लिक की मदद से काम करेगी। जल संरक्षण पर काम कर रही गैर सरकारी संस्थाओं ने ओरछा में वर्कशॉप आयोजित की। इस कार्यशाला में जल पुरुष राजेंद्र सिंह, मप्र के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल और जल संरक्षण पर काम करने वाले संजय सिंह तमाम एक्सपर्ट्स ने मंथन किया।

चंदेल राजाओं ने बनवाए बांध, तालाब और बावड़ियां: बुंदेलखंड मप्र और उप्र के 7-7 जिलों में बंटा हुआ है। इस इलाके में 9वीं से 16वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा है। पानी की कमी से यह इलाका हमेशा जूझता रहा है। चंदेल राजाओं ने बरसाती पानी को सहेजने के लिए 2 पहाड़ों के बीच पत्थर और मिट्?टी का प्रयोग करते हुए बांधों का निर्माण कराया। पहाड़ियों के तराई इलाके में बरसाती पानी इकट्?ठा हो सके। इन तालाबों को बनाने में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया। जिसमें एक तालाब के भरने पर वेस्टवियर के जरिए उसके तराई इलाके का तालाब भर सके। इन तालाबों के साथ ही बावड़ियां भी बनवाई गई। ताकि तालाबों और बांधों के किनारे की बावड़ियां भर सकें।

पंचायत मंत्री बोले- तालाबों का कैचमेंट बढ़ाएंगे: पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से कहा- लगातार चर्चाएं होती हैं वास्तविक स्थिति पर हमें जरुरी विचार करना

पड़ेगा। शुरू से यह बातें होती रहीं हैं। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और जो संस्थाएं जल के क्षेत्र में काम करती हैं। उनके साथ विमर्श करके हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। चूंकि, मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि रहा हूं तो मैंने देखा कि कैचमेंट की समस्या बढ़ी है। चाहे तालाबों में अतिक्रमण हो, या फिर सीसी रोड डाल दिया तो आने वाला बरसाती पानी अवरुद्ध हो गया। अगर पुलिया होती तो शायद पानी उसमें जाता। ये प्रयास इन कमियों को ठीक करने के लिए हैं।

पानी पर काम करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी: मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- उन तालाबों में डीसिल्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हैं। क्योंकि वहां का जो डेटा हमारे पुरखों ने बनाया उसमें कोई नुकसानदेह चीजें नहीं हैं। पानी की आवक को निरंतर करना। अगर कोई अतिक्रमण है तो उनको दूर करना। पानी आने के रास्तों को खोलने के लिए प्रशासनिक जरूरत पड़ती है। ऐसी कोई जानकारियां जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं या फिर जो जल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके कोई सुझाव हैं। जो भी सुझाव विमर्श में सामने आएंगे उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए पानी पर काम करना ही होगा। ये हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है।

पानी के रास्ते में बनी सड़कों पर विभाग बनवाएगा पुलिया: मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- हमें एक बार चिह्नित करना पड़ेगा कि हम शुरुआत कहां से करें। दमोह में मैंने किया था बेलाताल में एसपी के सामने पुलिया थी, उसे हमने तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि कैचमेंट खोलना हमारे नैतिक बल पर निर्भर करता है। प्रशासन की जरूरत तब पड़ेगी तब वहां कोई अवरोध पैदा करे। दूसरी बात ये है कि अगर सीसी रोड बना दिया तो वहां पुलिया बनानी पड़ेगी। ऐसे निर्माण की गारंटी हम जैसे मंत्रालय के लोग ही ले सकते हैं। आप बरसात के पहले पुलिया बना दो, अन्यथा वो फिर समस्या पैदा होगी। पानी आएगा तो रास्ता रुक जाएगा। हमारी मानवीय भूलों के कारण जो अवरोध पैदा हुए हैं। उसमें किसी बदलाव की जरूरत पड़ती है। तो फिर उसे हम अपने विभाग की प्राथमिकता में शामिल करेंगे। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा-मुझे लगता है कि पानी रोकने के बारे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। मैं नरसिंहपुर जिले से आता हूं। हमारे यहां बरसाती फसल नहीं होती थी। पूरे खेत भरे होते थे, न धान की फसल होती थी और न कुछ और होता था। उस कैचमेंट का परिणाम था कि हमारी सारी नदियां बारहमासी थीं। जब से हमने गन्ना की फसल, सोयाबीन की फसल बोने के कारण खेतों को भरना बंद किया है। आज हमारे जिले की सारी नदियां सूखने लगीं हैं।

पानी बचाने वाली जल सहेलियां निकाल रहीं 300 किमी की यात्रा: बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण पर काम करने वाली जल सहेलियों (महिलाओं के समूह) ने 2 फरवरी को ओरछा से यात्रा शुरू की है। जल सहेलियों की यह 18 दिवसीय यात्रा ओरछा के कंचना घाट से शुरू होकर छतरपुर के जटाशंकर धाम में पूरी होगी।

साढ़े चार साल में सौरभ ने शरद को बनाया करोड़पति

लोकायुक्त पूछताछ में कबूला- कई जमीनें खरीदी, बेचीं, चेतन भी अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर

भोपाल। आरटीओ का पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। उन्हें लोकायुक्त कोर्ट ने मंगलवार को जेल भेजा था। इससे पहले लोकायुक्त की टीम ने तीनों से 6 दिन तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ में शरद और चेतन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शरद ने बताया कि उसकी मुलाकात सौरभ से साढ़े चार साल पहले हुई थी। शरद ने यह भी कबूल किया कि सौरभ ने उसके कहने पर कई जमीनों की खरीद-फरोख्त की। वहीं, चेतन ने पूछताछ में बताया कि सौरभ ही उसे ग्वालियर से भोपाल लाया था।

शरद का कबूलनामा

स्वयं को आरटीओ अधिकारी बताता था सौरभ-लोकायुक्त की पूछताछ में शरद ने कहा- सौरभ से मेरी मुलाकात केवल साढ़े चार साल

पुरानी है। मैं पहले से कंस्ट्रक्शन फील्ड में था। रोहित तिवारी के नाम से सौरभ ने ई-7/78 नंबर बंगला खरीदा था। इस बंगले के मोडिफिकेशन का काम मैंने किया। सौरभ मेरे काम की अक्सर तारीफ करते थे। हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। शुरुआत में वह स्वयं को आरटीओ का अधिकारी बताते थे। धीरे-धीरे सौरभ को मेरे काम में रुचि जागने लगी।

अविरल कंस्ट्रक्शन में शरद और चेतन भागीदार

शरद ने कहा- सौरभ ने मुझे ऑफर दिया कि कंस्ट्रक्शन के बड़े ठेके उठाए जाएं। रुपए की कमी होने पर वे मदद करेंगे। इसके बाद हमने साथ काम शुरू किया। कई जमीनों की खरीद-फरोख्त सौरभ ने मेरे कहने पर की। इसे बेचकर मैंने रकम मुनाफा सहित लौटा दी। धीरे-धीरे उन्होंने मुझे होटल संचालन और रेस्टोरेंट बिजनेस की देखरेख का जिम्मा भी दिया। उन्होंने ही अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें चेतन और मुझे बराबरी का हिस्सेदार बताया। यह एकमात्र कंपनी है, जिसमें मैं और चेतन पार्टनर हैं।

शरद बोला- पूरी संपत्ति का हिसाब दे सकता हूं

अपनी बेगुनाही को सिद्ध करने के लिए शरद ने कहा- मैं अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब दे सकता हूं। उसने बताया कि चेतन, जयपुरिया स्कूल में सौरभ के साधारण कर्मचारी की हैसियत से दो कमरों में रहता था। उसके नाम पर जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वह सौरभ की है।

लता मंगेशकर की एक पेंटिंग में उनके 4359 चेहरे

तस्वीर बनाने वाले चित्रकार बोले- मैं, दीदी का भक्त, एशिया-इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज

जबलपुर (नप्र)। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम आपको मिलवाते हैं लता मंगेशकर के एक ऐसे फैन से, जिन्होंने लता मंगेशकर की एक नहीं, दो नहीं बल्कि सैकड़ों पेंटिंग बनाई हैं। इस फैन का नाम है रामकृपाल नामदेव, जिन्हें लता मंगेशकर के नाम ने इतनी प्रसिद्धि दिलाई कि आज पूरे भारत में उन्हें लता मंगेशकर के भक्त के नाम से जाना जाता है।

62 वर्षीय रामकृपाल नामदेव बीते 20 सालों से पेंटिंग कर रहे हैं। ऑयल पेंटिंग से लता दीदी की तस्वीर बनाने के लिए उनका नाम लिम्का, एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। खास बात यह है कि जब रामकृपाल ने लता मंगेशकर से मुलाकात कर उन्हें तस्वीर भेंट की थी, तो उनके मुंह से भी तारीफ में निकला, 'वाह, क्या फोटो है।'

स्वर कोकिला लता मंगेशकर की शायद ही कोई तस्वीर होगी, जिसे रामकृपाल नामदेव ने अपने ब्रश से कैनवास पर न उतारा हो। 6 फरवरी को रामकृपाल नामदेव ने पुरातत्व विभाग के कला वेदिका हॉल में लता मंगेशकर की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। रामकृपाल नामदेव

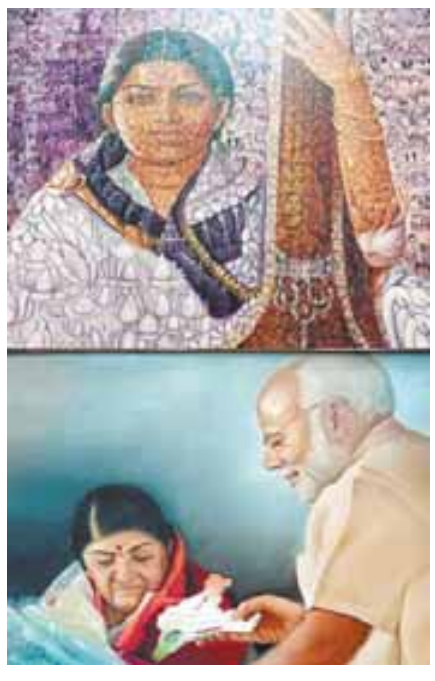

का कहना है कि वे लता मंगेशकर के गाने सुना करते थे। उनकी आवाज इतनी अच्छी लगने लगी कि लता मंगेशकर की पेंटिंग बनाने का विचार आया। उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग भी बनाई, जिसमें लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी उस समय की जितनी भी तस्वीरें थीं, सभी को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर तैयार की। इस तस्वीर को देशभर के लोगों ने सराहा और बाद में इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया।

एक तस्वीर में 1436 फोटोज से बनी

रामकृपाल नामदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं लता मंगेशकर का दीवाना नहीं बल्कि उनका भक्त हूं। जब तक जीवन रहेगा, उनकी भक्ति में लीन रहते हुए उनकी पेंटिंग बनाता रहूंगा। उन्होंने बताया, मैं 62 साल का हो चुका हूं, लेकिन मेरे हाथ आज भी निपुण हैं। जब कभी भी लता जी की तस्वीर बनाता हूं, तो पूरी तरह से उन पर खो जाता हूं।

2017 में पहली बार जबलपुर से प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो अब तक देश के कई राज्यों में लग चुकी है। रामकृपाल ने बताया कि उन्होंने यह प्रदर्शनी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में भी लगाई है। उनकी एक पेंटिंग, जिसमें लता मंगेशकर के 1436 चित्र हैं, 2019 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई थी।रामकृपाल नामदेव 20 सालों से पेंटिंग कर रहे हैं।

4359 चेहरे एक ही फोटो में

रामकृपाल नामदेव ने एक तस्वीर में लता मंगेशकर के 4359 चेहरे बनाए हैं। यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन उन्होंने यह कारनामा भी कर दिखाया। एक सेंटीमीटर की एक तस्वीर के हिसाब से हजारों तस्वीरों को एक बड़े चित्र में समेटने के लिए उन्हें लगभग 8 माह का समय लगा।

70 पेंटिंग्स में 6 हजार लता के चित्र

बीते 20 सालों से पेंटिंग कर रहे रामकृपाल ने बताया कि शौक के रूप में लता मंगेशकर की तस्वीर बनाना शुरू किया था, जो धीरे-धीरे जुनून बन गया। उन्होंने अब तक 70 से अधिक पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें 6000 से अधिक लता जी के चेहरे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि, छोटी-छोटी फोटो को बनाने के लिए एकाग्रता के साथ-साथ पतले ब्रश का उपयोग किया गया है।